नवसर्जन संस्कृति

PRGI No. GJHIN/25/A2786

नवसर्जन संस्कृति

PUBLISHED HIINDI DAILY FROM AHMEDABAD

वर्ष : 01
अंक : 258
दि. 21.06.2026, रविवार
पाना : 04
किंमत : 00.50 पैसा

घुसपैठ, विपक्ष और राष्ट्रीय सुरक्षा पर गरजे अमित शाह, बोले भारत में अवैध रूप से रहने वालों के लिए कोई जगह नहीं

मुंबई/कोल्हापुर। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने महाराष्ट्र के कोल्हापुर में आयोजित एक महत्वपूर्ण कार्यक्रम के दौरान राष्ट्रीय सुरक्षा, अवैध घुसपैठ, विपक्ष की राजनीति और देश की बदलती सुरक्षा नीति को लेकर तीखे राजनीतिक संदेश दिए। श्री अंबाबाई महालक्ष्मी मंदिर परिसर के संरक्षण, संवर्धन और विकास परियोजना के शुभारंभ अवसर पर आयोजित सभा में शाह ने जहां मंदिर विकास योजना को सांस्कृतिक विरासत से जोड़कर प्रस्तुत किया, वहीं विपक्षी दलों, विशेषकर कांग्रेस और शिवसेना (उद्धव ठाकरे गुट) पर भी जमकर निशाना साधा।
अपने संबोधन में उन्होंने अवैध घुसपैठ के मुद्दे को प्रमुखता से उठाते हुए कहा कि भारत कोई धर्मशाला नहीं है और देश में गैरकानूनी तरीके से रह रहे लोगों को पहचान कर बाहर निकाला जाएगा।
करीब 1,500 करोड़ रुपये की लागत से विकसित की जाने वाली महालक्ष्मी मंदिर परियोजना के शुभारंभ समारोह में महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे तथा महायुति सरकार के कई वरिष्ठ नेता उपस्थित थे। कार्यक्रम धार्मिक और सांस्कृतिक महत्व का था, लेकिन मंच से दिए गए राजनीतिक संदेशों ने इसे राष्ट्रीय स्तर की चर्चा का विषय बना दिया। अमित शाह ने अपने भाषण में कहा कि देश की सीमाओं की सुरक्षा और अवैध घुसपैठ पर नियंत्रण केंद्र सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकताओं में शामिल है। उन्होंने कहा कि जो लोग अवैध रूप से भारत में प्रवेश कर यहां रह रहे हैं, उनके खिलाफ कानून के अनुसार कार्रवाई की जाएगी।
शाह ने कहा कि देश की सुरक्षा और जनसांख्यिकीय संतुलन से जुड़े मुद्दों पर राजनीति नहीं होनी चाहिए, लेकिन कुछ राजनीतिक दल वोट बैंक की राजनीति के कारण ऐसे मामलों में स्पष्ट रुख अपनाने से बचते हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस और कुछ अन्य विपक्षी दल घुसपैठियों को राजनीतिक संरक्षण देने का प्रयास करते हैं

क्योंकि वे उन्हें संभावित वोट बैंक के रूप में देखते हैं। गृह मंत्री ने कहा कि राष्ट्रीय सुरक्षा के प्रश्न पर सरकार किसी भी प्रकार का समझौता नहीं करेगी और देश के कानूनों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कार्रवाई जारी रहेगी।
अपने भाषण में अमित शाह ने पश्चिम बंगाल का भी उल्लेख किया। उन्होंने दावा किया कि राज्य में बड़ी संख्या में लोग सीमा सुरक्षा और अवैध घुसपैठ के मुद्दे को लेकर चिंतित हैं। शाह ने कहा कि केंद्र सरकार सीमाओं की निगरानी को और अधिक मजबूत बनाने के लिए प्रतिबद्ध है तथा सीमा पार से होने वाली अवैध गतिविधियों को रोकने के लिए हर आवश्यक कदम उठाए जाएंगे। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय सीमाओं की सुरक्षा केवल सुरक्षा एजेंसियों का विषय नहीं, बल्कि देश की संप्रभुता और भविष्य से जुड़ा प्रश्न है।
राजनीतिक मोर्चे पर भी शाह ने विपक्ष को निशाने पर लिया। उन्होंने शिवसेना (उद्धव ठाकरे गुट) और कांग्रेस के गठबंधन पर टिप्पणी करते हुए कहा कि जिन दलों की विचारधारा कभी एक-दूसरे के विपरीत मानी जाती थी, वे अब सत्ता और राजनीतिक लाभ के लिए साथ आ गए हैं। उन्होंने कहा कि उद्धव ठाकरे ने कांग्रेस के साथ गठबंधन कर अपनी राजनीतिक दिशा बदल ली है। शाह ने आरोप लगाया कि सत्ता की राजनीति ने कई दलों को अपने मूल सिद्धांतों से दूर कर दिया है।
अपने संबोधन के दौरान अमित शाह ने महाराष्ट्र की राजनीति में हुए बदलावों का भी जिक्र किया। उन्होंने मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे की प्रशंसा करते हुए कहा कि अब महाराष्ट्र में शिवसेना के नाम को लेकर कोई भ्रम नहीं है। शाह ने दावा किया कि अब केवल एक ही शिवसेना है और उसका नेतृत्व एकनाथ शिंदे कर रहे हैं। यह बयान ऐसे समय आया है जब राज्य में शिवसेना की विरासत और राजनीतिक पहचान को लेकर लंबे समय से बहस चल रही है। शाह के इस बयान को महाराष्ट्र की राजनीति के संदर्भ में महत्वपूर्ण माना जा रहा है।
राष्ट्रीय सुरक्षा के मुद्दे पर बोलते हुए गृह मंत्री ने कांग्रेस नीत पूर्ववर्ती यूपीए सरकार की कार्यशैली की आलोचना की। उन्होंने कहा कि एक समय ऐसा था जब देश लगातार आतंकवादी हमलों का सामना कर रहा था, लेकिन केंद्र सरकार की प्रतिक्रिया कमजोर दिखाई देती थी। शाह ने कहा कि उस दौर में बड़े-बड़े आतंकी हमले हुए, अनेक निर्दोष नागरिकों की जान गई, लेकिन आतंकवाद के खिलाफ निर्णायक कार्रवाई देखने को नहीं मिली। उन्होंने पूर्व प्रधानमंत्री डॉ. मनमोहन सिंह के नेतृत्व वाली सरकार पर अप्रत्यक्ष रूप से निशाना साधते हुए कहा कि उस समय देश को जिस दृढ़ नेतृत्व की आवश्यकता थी, वह दिखाई नहीं दिया।
इसके विपरीत उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार की सुरक्षा नीति को अधिक आक्रामक और निर्णायक बताया। शाह ने कहा कि 2014 के बाद भारत की सुरक्षा रणनीति में बड़ा परिवर्तन आया है। उनके अनुसार, अब देश केवल आतंकी हमलों की निंदा करने तक सीमित नहीं रहता, बल्कि आवश्यक होने पर जवाबी कार्रवाई भी करता है। उन्होंने उरी और पुलवामा जैसे हमलों का उल्लेख करते हुए कहा कि इन घटनाओं के बाद भारत ने अपनी सैन्य क्षमता और राजनीतिक इच्छाशक्ति का प्रदर्शन किया। शाह ने दावा किया कि आज दुनिया भारत को एक ऐसे राष्ट्र के रूप में देखती है जो अपनी सुरक्षा और सम्मान की रक्षा के लिए आवश्यक कदम उठाने में सक्षम है।
अपने भाषण में अमित शाह ने भारत की रक्षा क्षमताओं का भी उल्लेख किया। उन्होंने कहा कि एक समय ऐसा था जब देश रक्षा क्षेत्र में काफी हद तक आयात पर निर्भर था, लेकिन आज भारत आत्मनिर्भरता की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है। शाह ने कहा कि रक्षा उत्पादन के क्षेत्र में देश ने उल्लेखनीय प्रगति की है और अब भारत आधुनिक मिसाइलों, रक्षा उपकरणों तथा रणनीतिक तकनीकों के विकास में महत्वपूर्ण उपलब्धियां हासिल कर रहा है। उनके अनुसार यह परिवर्तन केवल तकनीकी विकास का नहीं, बल्कि राष्ट्रीय आत्मविश्वास और सामरिक शक्ति के विस्तार का भी प्रतीक है।
कोल्हापुर में आयोजित यह कार्यक्रम मूल रूप से धार्मिक और सांस्कृतिक विकास परियोजना के शुभारंभ से जुड़ा था, लेकिन अमित शाह के भाषण ने इसे राष्ट्रीय राजनीति और सुरक्षा से जुड़े मुद्दों तक पहुंचा दिया। उनके संबोधन में विकास, सांस्कृतिक विरासत, राष्ट्रीय सुरक्षा, अवैध घुसपैठ, आतंकवाद और विपक्ष की राजनीति जैसे कई विषय शामिल रहे। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि आगामी चुनावी परिदृश्य को देखते हुए भाजपा राष्ट्रीय सुरक्षा और घुसपैठ जैसे मुद्दों को प्रमुखता से उठाने की रणनीति पर आगे बढ़ रही है।

ईसाई प्रार्थना केंद्र में बच्चों से दुर्व्यवहार का आरोप CWC जांच में सामने आए चौंकाने वाले खुलासे

पथानामथिट्टा। केरल के पथानामथिट्टा जिले में एक ईसाई प्रार्थना केंद्र से जुड़ा मामला गंभीर रूप लेता जा रहा है, जहां एक 17 वर्षीय लड़के द्वारा कर्मचारियों पर मारपीट के आरोप लगाए जाने के बाद बाल कल्याण समिति (CWC) की जांच में बच्चों के साथ कथित शोषण और दुर्व्यवहार से जुड़े कई चौंकाने वाले तथ्य सामने आए हैं। शुरुआती जांच के आधार पर समिति को यह संकेत मिले हैं कि केंद्र में रह रहे अन्य बच्चों के साथ भी अनुचित व्यवहार, मारपीट और कथित रूप से जबरन काम कराने जैसी घटनाएं हुई हो सकती हैं।
यह पूरा मामला 17 जून को तब सामने आया जब इडुक्की जिले के कट्टप्पना पुलिस स्टेशन में एक शिकायत दर्ज की गई। शिकायत में पथानामथिट्टा स्थित एलोहिम ग्लोबल वर्शिप सेंटर के तीन कर्मचारियों पर अनाक्कारा के रहने वाले एक 17 वर्षीय लड़के के साथ मारपीट का आरोप लगाया गया था। बताया गया कि यह लड़का आर्थिक रूप से कमजोर परिवार से आता है और उसे इस आश्वासन के साथ केंद्र में रखा गया था कि उसकी शिक्षा में सहायता की जाएगी और आगे चलकर उसे रोजगार के अवसर भी प्रदान किए जाएंगे।

पुलिस में मामला दर्ज होने के बाद जांच प्रक्रिया को आगे बढ़ाते हुए केस को पथानामथिट्टा जिले के एलावुमथिट्टा पुलिस स्टेशन को स्थानांतरित कर दिया गया। इसके बाद बाल कल्याण समिति ने भी इस पूरे प्रकरण की अलग से जांच शुरू की। CWC की अध्यक्ष लीना के. सुभाष ने मीडिया को बताया कि जांच के दौरान जो तथ्य सामने आए हैं, वे बेहद गंभीर प्रकृति के हैं और मामले की विस्तृत पड़ताल की जा रही है।
प्रारंभिक जांच में यह सामने आया कि केवल शिकायतकर्ता ही नहीं, बल्कि केंद्र में रह रहे अन्य बच्चों को भी कथित रूप से शारीरिक और मानसिक प्रताड़ना का सामना करना पड़ा हो सकता है। समिति ने केंद्र में रह रहे कुछ लोगों से बातचीत की, जिनमें वयस्क व्यक्ति भी शामिल थे। एक व्यक्ति का बयान दर्ज किया गया है, जबकि अन्य लोगों से भी पूछताछ की प्रक्रिया जारी है। इसके अलावा, जांच में यह भी पता चला कि केंद्र में कुछ लोग बिना उचित अनुमति के रह रहे थे, जिसमें एक बच्चा भी शामिल था, जिसे समिति ने वहां से सुरक्षित निकाल लिया है।
CWC के अनुसार, केंद्र में कुल तीन बच्चे मौजूद थे। इसके अतिरिक्त एक महिला और बच्चा भी वहां रहने की जानकारी सामने आई है, जिनकी वर्तमान स्थिति की जांच की जा रही है। अधिकारियों का कहना है कि इन सभी व्यक्तियों का पता लगाना और उनके बयान दर्ज करना जांच का महत्वपूर्ण हिस्सा है, ताकि यह स्पष्ट हो सके कि वहां वास्तव में क्या परिस्थितियां थीं और बच्चों के साथ किस प्रकार का व्यवहार किया जा रहा था।
जांच के दौरान एक और गंभीर आरोप सामने आया है कि कुछ बच्चों को उनकी शिक्षा और भविष्य सुधारने के नाम पर केंद्र में लाया गया था, लेकिन उन्हें अपेक्षित शैक्षिक सहायता प्रदान नहीं की गई। इसके बजाय, उन्हें केंद्र के भीतर काम करने के लिए मजबूर किए जाने के आरोप लगाए गए हैं। यह भी दावा किया गया है कि कई बच्चों को उनके काम के बदले कोई वेतन नहीं दिया गया।
एक बच्चे की चिकित्सा जांच में चोटों के निशान पाए जाने की पुष्टि भी की गई है, जिससे शारीरिक उत्पीड़न की आशंका और मजबूत हो गई है। CWC अध्यक्ष ने बताया कि बच्चों के बयान में भी मारपीट की बात सामने आई है। इन बयानों के आधार पर यह संकेत मिलते हैं कि केंद्र में अनुशासन या व्यवस्था के नाम पर कठोर और अनुचित व्यवहार किया जा रहा था।
पुलिस की प्रारंभिक जांच में यह भी सामने आया है कि आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों के बच्चों को शिक्षा और रोजगार के वादे के तहत केंद्र में लाया गया था। लेकिन वहां पहुंचने के बाद उनकी परिस्थितियां अपेक्षित सहायता के अनुरूप नहीं रहीं। पुलिस का कहना है कि 17 वर्षीय लड़का पिछले कुछ महीनों से इस केंद्र में रह रहा था और इसी दौरान उसके साथ कथित रूप से मारपीट की घटनाएं हुईं। इस मामले में किशोर न्याय (बच्चों की देखभाल और संरक्षण) अधिनियम के साथ-साथ भारतीय न्याय संहिता की संबंधित धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया है।

पेरियार नदी संरक्षण के लिए एकीकृत प्राधिकरण की जरूरत, हाईकोर्ट ने जताई गंभीर चिंता

कोच्चि। केरल हाईकोर्ट ने पेरियार नदी में बढ़ते प्रदूषण और पर्यावरणीय असंतुलन को लेकर गंभीर चिंता व्यक्त करते हुए स्पष्ट किया है कि इस महत्वपूर्ण नदी तंत्र के संरक्षण के लिए एक एकीकृत और समन्वित प्राधिकरण का गठन अब अनिवार्य हो चुका है। अदालत ने कहा कि पेरियार नदी केवल एक जलधारा नहीं है, बल्कि यह लाखों लोगों की जीवनरेखा है, और इसके बिगड़ते हालात को अनदेखा करना भविष्य में बड़े पर्यावरणीय संकट को आमंत्रण देने जैसा होगा।
मुख्य न्यायाधीश सौमेन सेन और न्यायमूर्ति श्याम कुमार वी.एम. की खंडपीठ ने मामले की सुनवाई के दौरान कहा कि नदी के संरक्षण और स्वच्छता के लिए कई एजेंसियां अलग-अलग स्तर पर काम कर रही हैं, लेकिन समन्वय की कमी के कारण प्रभावी परिणाम नहीं मिल पा रहे हैं। अदालत ने टिप्पणी की कि ऐसी स्थिति में एक यूनिफाइड अथॉरिटी का होना आवश्यक है, जो सभी संबंधित विभागों और एजेंसियों के बीच तालमेल स्थापित कर सके और नदी संरक्षण के कार्यों को एक साझा दिशा दे सके। अदालत ने यह भी कहा कि पेरियार नदी का महत्व केवल पर्यावरणीय नहीं, बल्कि सामाजिक और आर्थिक दृष्टि से भी अत्यंत व्यापक है। इस नदी पर न केवल पेयजल आपूर्ति निर्भर है, बल्कि कृषि, उद्योग और स्थानीय पारिस्थितिकी तंत्र भी इससे गहराई से जुड़े हुए हैं। ऐसे में यदि प्रदूषण की समस्या पर समय रहते नियंत्रण नहीं किया गया तो इसका प्रभाव व्यापक स्तर पर दिखाई देगा और लाखों लोगों का जीवन प्रभावित हो सकता है।

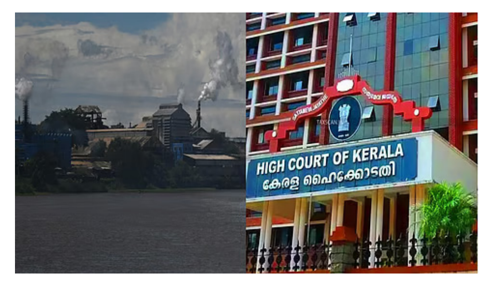

सुनवाई के दौरान अदालत ने सख्त शब्दों में कहा कि किसी बड़े संकट के इंतजार के बजाय अभी से ठोस और प्रभावी कदम उठाने की आवश्यकता है। न्यायालय ने कहा कि सभी संबंधित पक्षों को जिम्मेदारी से काम करते हुए न केवल प्रदूषण रोकने के उपाय करने चाहिए, बल्कि नदी के पुनर्जीवन के लिए दीर्घकालिक योजनाओं पर भी गंभीरता से कार्य करना चाहिए।
यह मामला उस जनहित याचिका पर आधारित है जिसमें आरोप लगाया गया है कि उद्योगों और अलुवा बाजार क्षेत्र से निकलने वाला अपशिष्ट और गंदा पानी सीधे पेरियार नदी में प्रवाहित किया जा रहा है, जिससे जल गुणवत्ता पर गंभीर प्रभाव पड़ रहा है। याचिका में मांग की गई है कि इस प्रकार के प्रदूषण पर तत्काल रोक लगाई जाए और जिम्मेदार संस्थाओं के खिलाफ कार्रवाई की जाए। अदालत ने इस मुद्दे को गंभीरता से लेते हुए केरल राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को भी निर्देश जारी किए हैं। न्यायालय ने बोर्ड से कहा है कि वह प्रस्तावित सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट (एसटीपी) की स्थापना के लिए एक नई और व्यावहारिक समयसीमा प्रस्तुत करे तथा यह सुनिश्चित करे कि निर्धारित समयसीमा का सख्ती से पालन किया जाए। अदालत ने यह भी स्पष्ट किया कि इस तरह की परियोजनाओं में देरी किसी भी स्थिति में स्वीकार्य नहीं है, क्योंकि इसका सीधा असर पर्यावरण और जनजीवन पर पड़ता है।
प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की ओर से अदालत को बताया गया कि पहले निर्धारित समयसीमा का पालन नहीं हो सका, जिसका एक कारण राज्य विधानसभा चुनावों से जुड़ी प्रशासनिक व्यस्तताएं भी रहीं। हालांकि अदालत ने इस स्पष्टीकरण पर गंभीर रुख अपनाते हुए संकेत दिया कि पर्यावरण संरक्षण जैसे महत्वपूर्ण मुद्दों को राजनीतिक या प्रशासनिक कारणों से टाला नहीं जा सकता।
न्यायालय ने कहा कि एसटीपी परियोजनाओं का समय पर पूरा होना पेरियार नदी के स्वास्थ्य के लिए अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि यह सीधे तौर पर जल की गुणवत्ता, जैव विविधता और पारिस्थितिकी संतुलन को प्रभावित करता है। नदी में प्रदूषण बढ़ने से न केवल जलीय जीवन पर असर पड़ता है, बल्कि आसपास के क्षेत्रों की वनस्पति और कृषि व्यवस्था भी प्रभावित होती है।
अदालत ने यह भी उल्लेख किया कि पेरियार नदी के किनारे बसे औद्योगिक और शहरी क्षेत्रों से लगातार बढ़ता अपशिष्ट प्रवाह स्थिति को और अधिक गंभीर बना रहा है। यदि इस पर नियंत्रण नहीं किया गया तो आने वाले वर्षों में यह समस्या और विकराल रूप ले सकती है।
राज्य सरकार द्वारा सितंबर 2025 में प्रस्तावित 'इंटीग्रेटेड रिवर बेसिन कंजर्वेशन एंड मैनेजमेंट प्लान' का उल्लेख करते हुए अदालत ने कहा कि यह पहल एक सकारात्मक कदम है, लेकिन इसे केवल दस्तावेजों तक सीमित नहीं रखा जाना चाहिए। इस योजना को प्रभावी रूप से लागू करने के लिए सभी संबंधित विभागों के बीच मजबूत समन्वय आवश्यक है।
विशेषज्ञों का मानना है कि पेरियार जैसी बड़ी नदियों के संरक्षण के लिए केवल नीतिगत घोषणाएं पर्याप्त नहीं होतीं, बल्कि जमीनी स्तर पर निरंतर निगरानी और क्रियान्वयन की आवश्यकता होती है। नदी के किनारे बसे औद्योगिक क्षेत्रों में अपशिष्ट प्रबंधन प्रणाली को सख्ती से लागू करना, अवैध निकासी पर रोक लगाना और स्थानीय समुदायों की भागीदारी सुनिश्चित करना भी इस दिशा में महत्वपूर्ण कदम हैं। अदालत ने मामले की अगली सुनवाई में नदी संरक्षण से जुड़े विभिन्न पहलुओं और एसटीपी परियोजना की प्रगति की विस्तृत समीक्षा करने का संकेत दिया है। फिलहाल अदालत का रुख यह स्पष्ट करता है कि वह पेरियार नदी के संरक्षण को लेकर किसी भी प्रकार की ढिलाई के पक्ष में नहीं है और इस दिशा में त्वरित और प्रभावी कार्रवाई की अपेक्षा कर रही है। इस पूरे मामले ने एक बार फिर यह सवाल खड़ा कर दिया है कि तेजी से बढ़ते शहरीकरण और औद्योगिकीकरण के बीच प्राकृतिक संसाधनों की सुरक्षा को कैसे संतुलित किया जाए।

हर साल 5,000 करोड़ टन रेत का दोहन, विकास की दौड़ में खो रही नदियों और तटों की सांस

नई दिल्ली। आधुनिक विकास की चमक-दमक के पीछे एक ऐसा संकट तेजी से गहराता जा रहा है, जिसकी तरफ दुनिया लंबे समय तक गंभीरता से ध्यान नहीं दे पाई। सड़कें, पुल, इमारतें और विशाल शहरी ढांचे खड़े करने के लिए जिस रेत का उपयोग सबसे अधिक होता है, वही रेत अब वैश्विक पर्यावरणीय असंतुलन का बड़ा कारण बनती जा रही है। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम (यूएनईपी) की ताजा रिपोर्ट ने इस संकट की भयावहता को और स्पष्ट कर दिया है। रिपोर्ट के अनुसार, दुनिया भर में हर साल लगभग 5,000 करोड़ टन रेत का दोहन किया जा रहा है, जो प्रकृति की पुनर्निर्माण क्षमता से कई गुना अधिक है।
यह आंकड़ा केवल एक संख्या नहीं, बल्कि उस गहरी खाई का संकेत है जो मानव विकास की तेज रफ्तार और प्राकृतिक संसाधनों की सीमित क्षमता के बीच लगातार बढ़ती जा रही है। वैज्ञानिकों का कहना है कि रेत बनने की प्रक्रिया अत्यंत धीमी होती है। चट्टानों के टूटने, नदी के प्रवाह और समुद्री तरंगों के प्राकृतिक क्षरण से रेत का निर्माण होता है, जिसमें लाखों वर्षों का समय लगता है। इसके विपरीत मानव सभ्यता कुछ ही दशकों में उतनी रेत निकाल रही है, जितनी प्रकृति सैकड़ों हजारों वर्षों में तैयार करती है।
रिपोर्ट के अनुसार शहरीकरण, जनसंख्या वृद्धि और बुनियादी ढांचे के तेज विस्तार के कारण रेत की मांग लगातार बढ़ रही है। अनुमान लगाया गया है कि वर्ष 2060 तक केवल निर्माण क्षेत्र में ही रेत की जरूरत लगभग 45 प्रतिशत तक बढ़ सकती है। इसका सीधा मतलब यह है कि आने वाले समय में यह संकट और अधिक गहराएगा, यदि इसके उपयोग और खनन को नियंत्रित

करने के लिए ठोस कदम नहीं उठाए गए।
विशेषज्ञों का मानना है कि रेत का संकट केवल संसाधन की कमी का मुद्दा नहीं है, बल्कि यह पर्यावरण, जैव विविधता और जल प्रणाली पर व्यापक प्रभाव डालने वाला विषय है। नदियों और समुद्री तटों से अत्यधिक रेत निकालने से उनके प्राकृतिक प्रवाह में बाधा उत्पन्न होती है। इससे नदी के किनारों का कटाव बढ़ता है, बाढ़ की संभावना अधिक होती है और समुद्री तटीय क्षेत्रों का संतुलन बिगड़ता है। कई स्थानों पर यह भी देखा गया है कि रेत के अत्यधिक दोहन के कारण समुद्र तट पीछे खिसक रहे हैं और गांव तथा शहर धीरे-धीरे समुद्री जल के खतरे में आ रहे हैं।
यूएनईपी की रिपोर्ट में एक और गंभीर तथ्य सामने आया है कि दुनिया की लगभग आधी ड्रेजिंग कंपनियां उन क्षेत्रों में भी रेत खनन कर रही हैं जिन्हें समुद्री संरक्षित क्षेत्र घोषित किया गया है। यह स्थिति इसलिए भी चिंताजनक है क्योंकि इन क्षेत्रों का उद्देश्य समुद्री पारिस्थितिकी तंत्र और जैव विविधता की रक्षा करना होता है। लेकिन रेत खनन की बढ़ती मांग ने इन संरक्षित क्षेत्रों को भी दबाव में ला दिया है।
रेत को अक्सर केवल निर्माण सामग्री के रूप में देखा जाता है, लेकिन पर्यावरण विशेषज्ञ इसे एक महत्वपूर्ण प्राकृतिक संसाधन मानते हैं जो पारिस्थितिकी तंत्र को संतुलित रखने में अहम भूमिका निभाता है। नदियों के तल और समुद्री तटों पर मौजूद रेत कई जीवों का प्राकृतिक आवास होती है। मछलियां, केकड़े, कछुए और अनेक प्रकार के सूक्ष्म जीव इन क्षेत्रों पर निर्भर रहते हैं। इसके अलावा रेत प्राकृतिक फिल्टर की तरह भी काम करती है, जो पानी को साफ करने और उसकी गुणवत्ता बनाए रखने में मदद करती है। जब यह प्राकृतिक संतुलन बिगड़ता है, तो इसका असर केवल पर्यावरण तक सीमित नहीं रहता, बल्कि मानव जीवन पर भी पड़ता है। भूजल स्तर प्रभावित होता है, जल की गुणवत्ता कम होती है और कई क्षेत्रों में पीने के पानी की समस्या गंभीर रूप ले लेती है। विशेषज्ञों का कहना है कि यदि यह स्थिति जारी रही, तो आने वाले दशकों में रेत का संकट तेल और पानी जैसे संसाधनों की तरह वैश्विक चिंता का विषय बन सकता है। रिपोर्ट में रेत के दो प्रकारों का उल्लेख भी किया गया है, जिसे वैज्ञानिक दृष्टि से समझना महत्वपूर्ण है। नदियों, डेल्टा और समुद्री तटों में मौजूद रेत को 'जिंदा रेत' कहा गया है, क्योंकि यह प्राकृतिक प्रक्रियाओं का हिस्सा बनी रहती है और पारिस्थितिकी तंत्र को समर्थन देती है। इसके विपरीत जब इस रेत को निकालकर सीमेंट, कंक्रीट या डामर जैसी निर्माण सामग्री में बदल दिया जाता है, तो वह हमेशा के लिए प्राकृतिक चक्र से बाहर हो जाती है। इसे 'मृत रेत' कहा गया है। यह परिवर्तन स्थायी होता है और इसका पुनर्निर्माण संभव नहीं होता।
शहरी विकास और औद्योगिकीकरण के इस दौर में रेत की मांग लगातार बढ़ रही है। बड़े-बड़े शहरों में गगनचुंबी इमारतों का निर्माण, सड़क नेटवर्क का विस्तार और औद्योगिक ढांचे का विकास सीधे तौर पर रेत पर निर्भर करता है। यही कारण है कि कई देशों में अवैध रेत खनन भी एक गंभीर समस्या बन चुका है। कई स्थानों पर संगठित और असंगठित दोनों तरह से रेत का अवैध व्यापार चल रहा है, जिससे न केवल पर्यावरण को नुकसान पहुंच रहा है, बल्कि स्थानीय समुदायों की आजीविका भी प्रभावित हो रही है। पर्यावरणविदों का मानना है कि इस समस्या का समाधान केवल प्रतिबंधों से नहीं, बल्कि वैकल्पिक निर्माण सामग्री और टिकाऊ विकास मॉडल अपनाने से ही संभव है। कई देशों में पुनर्चक्रित निर्माण सामग्री और रेत के विकल्प पर शोध भी किया जा रहा है, ताकि प्राकृतिक रेत पर निर्भरता को कम किया जा सके। हालांकि अभी यह प्रयास प्रारंभिक चरण में हैं और व्यापक स्तर पर इनका उपयोग नहीं हो पाया है। यूएनईपी की यह रिपोर्ट दुनिया को एक स्पष्ट चेतावनी देती है कि यदि रेत के अनियंत्रित दोहन पर नियंत्रण नहीं लगाया गया, तो इसका असर केवल पर्यावरण तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि यह मानव सभ्यता की स्थिरता और भविष्य के विकास मॉडल को भी प्रभावित करेगा। नदियों का सूखना, समुद्री तटों का क्षरण, जैव विविधता का नुकसान और जल संकट जैसी समस्याएं एक साथ गहराने लगेंगी। आज आवश्यकता इस बात की है कि विकास और पर्यावरण के बीच संतुलन स्थापित किया जाए। रेत जैसे बुनियादी लेकिन सीमित संसाधन को केवल निर्माण सामग्री के रूप में देखने के बजाय एक पारिस्थितिक संपदा के रूप में समझना होगा।

देश-दुनिया के नवीनतम समाचार प्राप्त करने के लिए आज ही नवसर्जन संस्कृति हिंदी चेनल देखिये

संपादकीय

हरियाणा में बिना प्रदूषण नियंत्रकों के हजारों इकाइयां

इस बात में दो राय नहीं कि हरियाणा की समृद्धि में औद्योगिक विकास की बड़ी भूमिका रही है। जिसमें बड़ी संख्या में राज्य के लोगों को रोजगार भी मिला है। हरियाणा अपनी औद्योगिक सफलता की प्रेरक कहानी पर गर्व करता रहा है। मानेसर के ऑटोमोबाइल हब से लेकर राज्य भर में फैले मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर के उद्योगों में बड़े पैमाने पर नौकरियों के अवसर पैदा हुए हैं। निस्संदेह, इससे राज्य के आर्थिक विकास को भी गति मिली है। लेकिन इस विकास की दूसरी तस्वीर चिंता बढ़ाने वाली है। हरियाणा राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की यह बात चिंतित करने वाली है कि राज्य में तीन हजार औद्योगिक इकाइयों में वायु प्रदूषण को नियंत्रित करने वाले पर्याप्त उपकरण ही नहीं लगे हैं। जो एक गंभीर स्थिति को दर्शाती है। निस्संदेह, कोई भी विकास साफ हवा की कीमत पर नहीं किया जाना चाहिए। चिंता की बात यह भी है कि प्रदूषण नियामक उपकरणों की कमी वाली औद्योगिक इकाइयों की सूची में मानेसर सबसे ऊपर पाया गया है। यह औद्योगिक टाउनशिप न केवल हरियाणा का प्रमुख आर्थिक इंजन है, बल्कि हजारों श्रमिकों और उनके परिवारों का घर भी है। जो आज हर दिन कारखानों से निकलने वाले धुएं से प्रभावित हवा में सांस लेने को अभिशप्त हैं। विडंबना यह है कि अब तक इस संकट को गंभीरता से नहीं लिया गया। इस स्थिति को सुधारने के लिये कोई सार्थक पहल भी नहीं हुई है। बड़ी विचित्र बात है कि गाहे-बगाहे हर साल मौसमी स्मॉग या पराली जलाने को लेकर आरोप-प्रत्यारोपों का सिलसिला चलता रहता है। जबकि कोई वैज्ञानिक अध्ययन भी हमारे सामने नहीं आया कि स्मॉग व पराली जलाने की राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में होने वाले प्रदूषण में कितनी भूमिका होती है। लेकिन जिन औद्योगिक इकाइयों से निकलने वाले प्रदूषण को हम नाप कर नियंत्रित कर सकते हैं, उस दिशा में कोई सार्थक पहल नहीं की गई। सालभर चलने वाली औद्योगिक उत्सर्जन की समस्या को प्राथमिकता के आधार पर संबोधित किया जाना चाहिए।

यह तथ्य किसी से छिपा नहीं है कि वर्ष पर्यंत होने वाले औद्योगिक उत्सर्जन से हवा की गुणवत्ता खराब ही होती है। जिससे सांस संबंधी रोगों को बढ़ावा मिलता है। ये स्थितियां लोगों के जीवन की गुणवत्ता में गिरावट ही पैदा करती हैं। विडंबना यह है कि पर्यावरण की दृष्टि से बेहद संवेदनशील इलाकों, विशेष रूप से देश के नेशनल कैपिटल रीजन यानी एनसीआर में काम करने वाली औद्योगिक इकाइयों को अपनी जिम्मेदारी व जवाबदेही का अच्छे से पता होता है। यह दुर्भाग्यपूर्ण ही है कि इसके बावजूद हजारों इकाइयां नियमों को ताक पर रखकर मुनाफा कमाने में लगी हैं, वह भी हजारों लोगों की सांसों की कीमत पर। यह नियामक तंत्र द्वारा नियमों को लागू करने और जवाबदेही तय करने में बड़ी नाकामी को ही दर्शाता है। इस जटिल समस्या का समाधान सिर्फ नोटिस जारी करने तक सीमित नहीं होना चाहिए। वह बात अलग है कि कुछ छोटी और मध्यम दर्जे की कंपनियों को साफ-सुथरी टेक्नोलॉजी अपनाने के लिये तकनीकी सहायता और आर्थिक मदद की जरूरत हो सकती है। इसके बावजूद प्रदूषणरोधी उपकरण लगाने की समय-सीमा और निर्धारित मानकों को लेकर किसी तरह का समझौता नहीं किया जा सकता। सही मायने में चेतावनी के बावजूद बार-बार नियमों का उल्लंघन करने वालों पर कड़ा जुर्माना लगाया जाना चाहिए। यह एक हकीकत है कि साफ हवा औद्योगिक विकास में कोई बाधा उत्पन्न नहीं करती है। यही स्थायी व दूरगामी परिणामों वाले विकास की अपरिहार्य शर्त भी है। सही मायनों में हरियाणा की अर्थव्यवस्था तब तक फल-फूल नहीं सकती, जब तक यहां के लोगों को अपनी सेहत की कीमत पर यह विकास करना पड़े। इसमें दो राय नहीं कि प्रगति और विकास की दृष्टि से राज्य के उद्योगों ने अग्रणी भूमिका निभाई है। इन उद्यमियों ने इनोवेशन और प्रतिस्पर्धा की कसौटी पर अपनी बेहतर क्षमताओं को साबित किया भी है। अब उन्हें इस बात के लिये प्रेरित करना होगा कि वे अब पर्यावरण के प्रति जिम्मेदारी निभाने में भी वैसी ही प्रतिबद्धता दर्शाएं। सही मायने में किसी भी समाज में असली समृद्धि तभी आ सकती है जब हमारी प्राथमिकताओं में जन-स्वास्थ्य पहले हो।

INS Dunagiri, INS Sanshodhak और INS Agray के जरिये समुद्र पर भी राज करेगा भारत

> “इन तीनों युद्धपोतों की सबसे बड़ी खासियत यह है कि इन्हें भारतीय नौसेना के युद्धपोत डिजाइन ब्यूरो ने तैयार किया है और कोलकाता स्थित गार्डन रीच शिपबिल्डर्स एंड इंजीनियर्स ने निर्मित किया है। इन जहाजों में 75 प्रतिशत से अधिक स्वदेशी सामग्री का उपयोग हुआ है।

कोलकाता के श्यामा प्रसाद मुखर्जी बंदरगाह पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारतीय नौसेना को तीन ताकतवर स्वदेशी युद्धपोत दुनागिरी, संशोधक और अग्रय सौंपेंगे। यह नौसेना में सिर्फ तीन नए जहाजों के शामिल होने का कार्यक्रम नहीं, बल्कि हिंद महासागर में भारत की बढ़ती समुद्री ताकत और आत्मनिर्भर रक्षा क्षमता का बड़ा प्रदर्शन भी माना जा रहा है। स्वदेशी तकनीक से बने ये तीनों युद्धपोत समुद्री युद्ध, समुद्री निगरानी और पनडुब्बियों से मुकाबले में भारतीय नौसेना को नई ताकत देने वाले साबित होंगे।इन तीनों युद्धपोतों की सबसे बड़ी खासियत यह है कि इन्हें भारतीय नौसेना के युद्धपोत डिजाइन ब्यूरो ने तैयार किया है और कोलकाता स्थित गार्डन रीच शिपबिल्डर्स एंड इंजीनियर्स ने निर्मित किया है। इन जहाजों में 75 प्रतिशत से अधिक स्वदेशी सामग्री का उपयोग हुआ है। इस परियोजना में दो सौ से अधिक सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योगों की भागीदारी ने यह स्पष्ट कर दिया है कि भारत अब रक्षा आयात पर निर्भर रहने वाला देश नहीं, बल्कि अत्याधुनिक युद्धक क्षमता विकसित करने वाली शक्ति बन चुका है। हम आपको बता दें कि तीनों प्लेटफार्म अपने आप में अलग सामरिक जिम्मेदारियां निभाने वाले समुद्री हथियार हैं। दुनागिरी जहां गहरे समुद्र में आक्रामक युद्ध क्षमता का प्रतीक है, वहीं संशोधक समुद्री खुफिया और महासागरीय जानकारी जुटाने का अत्याधुनिक साधन है। दूसरी ओर अग्रय तटीय क्षेत्रों में दुश्मन की पनडुब्बियों का शिकार करने वाला घातक हथियार है। इन तीनों को एक साथ नौसेना में शामिल करना इस बात का संकेत है कि भारत अब समुद्री सुरक्षा को केवल युद्ध तक सीमित नहीं देख रहा, बल्कि निगरानी, सूचना वर्चस्व और समुद्री प्रभुत्व की व्यापक रणनीति पर काम कर रहा है।

हम आपको बता दें कि दुनागिरी परियोजना सत्रह ए के तहत निर्मित पांचवां स्टील्थ युद्धपोत है। इसकी बनावट ऐसी है कि दुश्मन के राडार इसे आसानी से पकड़ नहीं सकते। इसमें ब्रह्मोस सुपरसोनिक प्रहारक मिसाइलें और मध्यम दूरी की वायु रक्षा प्रणाली तैनात है। इसका अर्थ यह है कि यह युद्धपोत समुद्र से दुश्मन के जहाजों, ठिकानों और हवाई खतरों पर एक साथ हमला करने में सक्षम है। हिंद महासागर में चीन की बढ़ती मौजूदगी और पाकिस्तान की नौसैनिक गतिविधियों को देखते हुए दुनागिरी का शामिल होना भारतीय नौसेना की मारक क्षमता को कई गुना बढ़ाने वाला कदम माना जा रहा है। रणनीतिक नजरिये से देखें तो यह युद्धपोत भारत की ब्लू वाटर क्षमता को मजबूत करेगा। ब्लू वाटर क्षमता का मतलब केवल तटों की रक्षा नहीं, बल्कि हजारों किलोमीटर दूर समुद्री क्षेत्रों में भी सैन्य प्रभाव बनाए रखना होता है। भारत लंबे समय से हिंद महासागर क्षेत्र में अपनी निर्णायक मौजूदगी स्थापित करना चाहता है और दुनागिरी उसी दिशा में एक मजबूत कदम है।

वहीं संशोधक का महत्व अपेक्षाकृत शांत लेकिन अत्यंत गहरा है। यह विशाल सर्वेक्षण पोत समुद्र की सतह के नीचे की दुनिया का मानचित्र तैयार करेगा। इसमें स्वचालित जलयान, दूर नियंत्रित यंत्र और अत्याधुनिक सर्वेक्षण प्रणाली लगी हुई हैं। यह समुद्री गहराई, समुद्र तल की बनावट, जलधाराओं और भूभौतिकीय आंकड़ों का संग्रह करेगा।

सामरिक दृष्टि से यह जानकारी युद्ध के समय बेहद महत्वपूर्ण होती है। पनडुब्बियों की आवाजाही, समुद्री सुरंगों की पहचान और नौसैनिक मार्गों की सुरक्षा इसी तरह के आंकड़ों पर निर्भर करती है। यही कारण है कि समुद्री सर्वेक्षण पोतों को आधुनिक नौसैनिक युद्ध का मौन हथियार कहा जाता है। नागरिक उपयोग में भी संशोधक समुद्री व्यापार मार्गों, बंदरगाह विकास और आपदा प्रबंधन के लिए अहम भूमिका निभाएगा।

साथ ही अग्रय भारतीय नौसेना की तटीय सुरक्षा रणनीति का सबसे तेज और घातक हिस्सा माना जा रहा है। यह अर्णाला श्रेणी का पनडुब्बी रोधी युद्धपोत है, जिसे उथले समुद्री क्षेत्रों में दुश्मन की पनडुब्बियों का पता लगाने और उन्हें नष्ट करने के लिए तैयार किया गया है। इसमें हल्के टॉरपीडो, स्वदेशी रॉकेट प्रक्षेपक और उथले पानी में काम करने वाली सोनार प्रणाली लगी है। देखा जाये तो आज के दौर में पनडुब्बियां समुद्री युद्ध का सबसे खतरनाक हथियार मानी जाती हैं। चीन हिंद महासागर में लगातार अपनी पनडुब्बियों की गतिविधियां बढ़ा रहा है। पाकिस्तान भी चीनी सहयोग से अपनी पनडुब्बी क्षमता मजबूत कर रहा है। ऐसे में अग्रय जैसे युद्धपोत भारत की समुद्री सीमाओं के लिए सुरक्षा कवच साबित होंगे। खासकर बंगाल की खाड़ी और अरब सागर जैसे संवेदनशील क्षेत्रों में इसकी भूमिका निर्णायक मानी जा रही है।

देखा जाये तो इन तीनों युद्धपोतों का एक साथ नौसेना में शामिल होना केवल सैन्य उपलब्धि नहीं, बल्कि रणनीतिक संदेश भी है। भारत दुनिया को यह बता रहा है कि वह अब समुद्री शक्ति संतुलन में निर्णायक भूमिका निभाने के लिए तैयार है। हिंद महासागर क्षेत्र में चीन की विस्तारवादी नीति, समुद्री व्यापार मार्गों की सुरक्षा, ऊर्जा आपूर्ति की रक्षा और समुद्री निगरानी जैसे मुद्दों ने नौसैनिक ताकत को पहले से कहीं अधिक महत्वपूर्ण बना दिया है।

सबसे महत्वपूर्ण पहलू यह है कि भारत ने यह क्षमता विदेशी तकनीक के सहारे नहीं, बल्कि अपने दम पर विकसित की है। आत्मनिर्भर भारत अभियान का वास्तविक चेहरा अब रक्षा क्षेत्र में दिखाई देने लगा है। युद्धपोत निर्माण से लेकर हथियार प्रणालियों तक स्वदेशीकरण का यह विस्तार आने वाले वर्षों में भारत को वैश्विक रक्षा निर्यातक भी बना सकता है। बहरहाल, कोलकाता में होने वाला यह समारोह इसलिए ऐतिहासिक है क्योंकि यह केवल जहाजों का शामिल होना नहीं, बल्कि भारत की समुद्री महत्वाकांक्षा, सैन्य आत्मविश्वास और रणनीतिक उभार का सार्वजनिक उद्घोष है। हिंद महासागर में अब भारत केवल चौकसी नहीं करेगा, बल्कि नेतृत्व की भूमिका निभाने की तैयारी में दिखाई दे रहा है।

प्रेरणा

मन की शक्ति का कमाल

सफलता का रास्ता केवल प्रतिभा, भाग्य या संसाधनों से नहीं बनता, बल्कि उस शक्ति से बनता है जो व्यक्ति के भीतर छिपी होती है। यह शक्ति है एकाग्रता की शक्ति। संसार में जितने भी महान आविष्कार हुए, जितनी भी बड़ी उपलब्धियाँ हासिल की गईं और जितने भी लोग इतिहास में अमर हुए, उनके जीवन में एक बात समान थी—अपने लक्ष्य के प्रति अटूट एकाग्रता। जब मन एक दिशा में केंद्रित हो जाता है, तब वह असाधारण परिणाम उत्पन्न करता है। लेकिन जब वही मन अनेक दिशाओं में भटकता रहता है, तो उसकी ऊर्जा बिखर जाती है और व्यक्ति अपनी वास्तविक क्षमता का उपयोग नहीं कर पाता। तमिलनाडु के एक विद्यालय में पढ़ने वाली एक छोटी-सी छात्रा एन. वेल्लारमथी भी उस दिन शायद यह नहीं जानती थी कि एक साधारण कक्षा में मिली शिक्षा उसके जीवन का मार्ग बदल देगी। वह अपनी कक्षा में बैठी थी और अन्य विद्यार्थियों की तरह अपने शिक्षक की बातें ध्यान से सुन रही थी। उस दिन का पाठ स्वामी विवेकानंद के जीवन और विचारों पर आधारित था। शिक्षिका बड़े उत्साह से बच्चों को समझा रही थीं कि स्वामी विवेकानंद केवल एक महान संन्यासी ही नहीं थे, बल्कि युवाओं के लिए प्रेरणा के सबसे बड़े स्रोतों में से एक थे।

शिक्षिका ने बच्चों से कहा, “स्वामी विवेकानंद का मानना था कि यदि उन्हें फिर से शिक्षा प्राप्त करने का अवसर मिले, तो वे केवल जानकारी और तथ्यों को याद करने पर ध्यान नहीं देंगे। वे सबसे पहले अपनी एकाग्रता की शक्ति को विकसित करेंगे। उनका विश्वास था कि एकाग्र मन किसी भी लक्ष्य को प्राप्त कर सकता है।”

यह सुनकर बच्चों की जिज्ञासा बढ़ गई। शिक्षिका ने आगे कहा, “स्वामी विवेकानंद एकाग्रता की तुलना सूर्य की किरणों से करते थे। सूर्य की किरणें पूरे आकाश में फैली रहती हैं, लेकिन जब उन्हें किसी एक बिंदु पर केंद्रित किया जाता है, तब वे अद्भुत शक्ति उत्पन्न करती हैं।”

बच्चों को यह बात पूरी तरह समझ नहीं आई। तब शिक्षिका ने एक छोटा-सा प्रयोग करने का निर्णय लिया। उन्होंने एक लेंस लिया और उसके नीचे एक सफेद कागज़ रखा। फिर सूर्य की किरणों को उस लेंस की सहायता से एक बिंदु पर केंद्रित किया। कुछ ही क्षणों बाद कागज़ से धुआँ उठने लगा और देखते ही देखते उसमें आग लग गई।

पूरा वर्ग आश्चर्य से भर उठा। बच्चों की आँखें फैल गईं। नन्ही वेल्लारमथी उत्साहित होकर बोली, “मैडम, यह तो चमत्कार है!” शिक्षिका मुस्कुराईं और बोलीं, “नहीं, यह कोई चमत्कार नहीं है। यह एकाग्रता की शक्ति है। सूर्य की किरणें पहले भी उतनी ही शक्तिशाली थीं, लेकिन जब तक वे बिखरी हुई थीं, तब तक कोई विशेष प्रभाव नहीं दिखा। जैसे ही वे एक बिंदु पर केंद्रित हुईं, उन्होंने कागज़ को जला दिया। यही बात मनुष्य के मन पर भी लागू होती है। यदि हमारा ध्यान हर समय इधर-उधर भटकता रहेगा, तो हम अपनी शक्ति का पूरा उपयोग नहीं कर पाएंगे। लेकिन यदि हम अपने लक्ष्य पर पूरी तरह केंद्रित हो जाएँ, तो जीवन में कोई भी उपलब्धि असंभव नहीं रहेगी।”

यह बात वेल्लारमथी के मन में गहराई तक उतर गई। वह केवल एक प्रयोग नहीं था, बल्कि जीवन का एक महत्वपूर्ण संदेश था। उस दिन के बाद उसने अपनी पढ़ाई को केवल एक जिम्मेदारी नहीं, बल्कि अपने सपनों तक पहुँचने का माध्यम मान लिया। उसने निश्चय किया कि चाहे कितनी भी कठिनाइयाँ आएँ, वह अपने लक्ष्य से ध्यान नहीं हटाएगी।

समय के साथ उसकी मेहनत और लगन बढ़ती गई। जब उसके साथी कभी-कभी निराश हो जाते या अपने लक्ष्य बदल लेते, तब भी वेल्लारमथी अपने मार्ग पर डटी रही। उसने अपने भीतर अनुशासन विकसित किया। वह जानती थी कि सफलता अचानक नहीं मिलती, बल्कि लगातार किए गए छोटे-छोटे प्रयासों का परिणाम होती है। उसने हर दिन को अपने सपनों के करीब पहुँचने का अवसर माना।

उसकी यही एकाग्रता और समर्पण उसे भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन, इसरो तक ले गए। यह वही संस्था है जिसने भारत को अंतरिक्ष विज्ञान के क्षेत्र में विश्व की अग्रणी शक्तियों में शामिल किया। इसरो में काम करना किसी भी वैज्ञानिक का सपना होता है, और वेल्लारमथी ने यह सपना अपनी मेहनत से पूरा किया।

लेकिन उसकी उपलब्धियाँ यहीं नहीं रुकीं। उसने अपने ज्ञान, कौशल और नेतृत्व क्षमता के बल पर एक नई पहचान बनाई। वह आरआईएसएटी-1 उपग्रह की पहली महिला परियोजना निदेशक बनीं। यह उपलब्धि केवल व्यक्तिगत सफलता नहीं थी, बल्कि भारतीय महिलाओं की क्षमता और प्रतिभा का भी प्रमाण थी। उन्होंने यह दिखा दिया कि यदि मन में दृढ़ निश्चय हो, तो कोई भी बाधा रास्ता नहीं रोक सकती।

वेल्लारमथी की पहचान एक और विशेष कारण से बनी। जब भी श्रीहरिकोटा स्थित सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से कोई रॉकेट प्रक्षेपित किया जाता था, तो उसकी उल्टी गिनती की आवाज़ देशभर में सुनाई देती थी। वह आत्मविश्वास से भरी आवाज़ वेल्लारमथी की होती थी। उनकी स्पष्ट और प्रभावशाली प्रस्तुति के कारण लोग उन्हें “इसरो की आवाज़” कहने लगे।

एक छोटी-सी छात्रा से लेकर देश की प्रतिष्ठित वैज्ञानिक बनने तक का उनका सफर यह सिद्ध करता है कि महान उपलब्धियाँ किसी एक दिन में नहीं मिलतीं। वे वर्षों की एकाग्रता, अनुशासन और निरंतर प्रयास का परिणाम होती हैं। यदि उन्होंने बचपन में सीखी गई उस सीख को भुला दिया होता, तो शायद वे इतनी ऊँचाइयों तक नहीं पहुँच पातीं।

आज का युग अवसरों के साथ-साथ चुनौतियों का भी युग है। आधुनिक तकनीक ने हमारे जीवन को आसान बनाया है, लेकिन उसने हमारे ध्यान को भटकाने के अनेक साधन भी दिए हैं। मोबाइल फोन, सोशल मीडिया, मनोरंजन के अनगिनत माध्यम और निरंतर आने वाली सूचनाएँ हमारे मन को एक जगह टिकने नहीं देतीं। ऐसे समय में एकाग्रता का महत्व पहले से कहीं अधिक बढ़ गया है। जो विद्यार्थी पढ़ाई करते समय बार-बार अपना ध्यान बदलते हैं, वे अक्सर अपेक्षित परिणाम प्राप्त नहीं कर पाते। इसके विपरीत जो विद्यार्थी सीमित समय के लिए भी पूरी एकाग्रता के साथ अध्ययन करते हैं, वे अधिक सफल होते हैं। यही सिद्धांत जीवन के हर क्षेत्र में लागू होता है। चाहे कोई खिलाड़ी हो, कलाकार हो, वैज्ञानिक हो या व्यवसायी, सफलता उसी को मिलती है जो अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित रखता है।

एकाग्रता का अर्थ केवल पढ़ाई तक सीमित नहीं है। इसका अर्थ है अपने उद्देश्य को स्पष्ट रखना और उस दिशा में लगातार प्रयास करते रहना। जब व्यक्ति अपने मन को नियंत्रित करना सीख लेता है, तब परिस्थितियाँ उसकी प्रगति को रोक नहीं पातीं। उसका आत्मविश्वास बढ़ता है, उसकी कार्यक्षमता बढ़ती है और उसके सपने वास्तविकता में बदलने लगते हैं। वेल्लारमथी की प्रेरक यात्रा हमें सिखाती है कि जीवन में सफलता का सबसे बड़ा रहस्य किसी जादुई सूत्र में नहीं, बल्कि मन की शक्ति में छिपा है। जिस प्रकार लेंस से केंद्रित सूर्य किरणें साधारण कागज़ को जला सकती हैं, उसी प्रकार एकाग्र मन साधारण व्यक्ति को असाधारण बना सकता है।

आधुनिक संकटों का प्राचीन समाधान है योग

दुनिया भर के 170 से भी ज्यादा देश प्रतिवर्ष 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में मनाते हैं और योग को अपनी दिनचर्या का हिस्सा बनाने का संकल्प लेते हैं। संयुक्त राष्ट्र ने संयुक्त राष्ट्र महासभा के 69वें सत्र में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा रखे गए प्रस्ताव के जवाब में 11 दिसंबर 2014 को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की स्थापना की थी और वैश्विक स्तर पर पहला अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 21 जून 2015 को मनाया गया था। इस वर्ष पूरी दुनिया ‘स्वस्थ वृद्धावस्था के लिए योग’ थीम के साथ 12वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मना रही है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का यह विषय जीवन के सभी चरणों में शारीरिक शक्ति, मानसिक अनुकूलता और समग्र कल्याण को बढ़ावा देने में योग की भूमिका का उल्लेख करता है। योग व्यक्तियों को स्वस्थ और अधिक संतुलित जीवन जीने के लिए प्रेरित करता रहता है, साथ ही आंतरिक शक्ति और जागरूकता को भी बढ़ावा देता है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के उपलक्ष्य में भारतीय वायुसेना देशभर में योगाभ्यास का आयोजन करेगी, जिसमें उत्तर में लेह के ऊंचे पहाड़ों से लेकर दक्षिण में कार निकोबार के समुद्र तटों तक और पूर्वी सीमांत तवांग से लेकर पश्चिम में पवित्र शहर द्वारका तक के विविध भूभाग शामिल होंगे। प्रतिवर्ष यह दिवस मनाने का उद्देश्य योग को एक ऐसे आंदोलन के रूप में बढ़ावा देना है, जो व्यक्ति की तन्यकता को उन्नत करता है और समाज के प्रत्येक व्यक्ति के लिए कल्याण को बढ़ावा देता है। वैसे तो योग को विश्व स्तर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सतत प्रयासों के चलते वर्ष 2015 में अपनाया गया था किंतु भारत में योग का इतिहास सदियों पुराना है। माना जाता रहा है कि पृथ्वी पर सभ्यता की शुरुआत से ही योग किया जा रहा है लेकिन साक्ष्यों की बात करें तो योग करीब पांच हजार वर्ष पुरानी भारतीय परंपरा है। करीब 2700 ईसा पूर्व वैदिक काल में और उसके बाद पतंजलि काल तक योग की मौजूदगी के ऐतिहासिक प्रमाण मिलते हैं। महर्षि पतंजलि ने अभ्यास तथा वैराग्य द्वारा मन की वृत्तियों पर नियंत्रण करने को ही योग बताया था। हिंदू धर्म शास्त्रों में भी योग का व्यापक उल्लेख मिलता है। विष्णु पुराण में कहा गया है कि जीवात्मा तथा परमात्मा का पूर्णतया मिलन ही अद्वेतानुभूति योग कहलाता है। इसी प्रकार भगवद्गीता बोध में वर्णित है कि दुःख-सुख, पाप-पुण्य, शत्रु-मित्र, शीत-उष्ण आदि द्वंदों से अतीतय मुक्त होकर सर्वत्र समभाव से व्यवहार करना ही योग है। भारत में योग को निरोगी रहने की करीब पांच हजार वर्ष पुरानी मानसिक, शारीरिक और आध्यात्मिक पद्धति के रूप में मान्यता प्राप्त है, जो भारतीयों की जीवनचर्या का अहम हिस्सा है। सही मायनों में योग भारत के पास प्रकृति प्रदत्त ऐसी अमूल्य धरोहर है, जिसका भारत सदियों से शारीरिक और मानसिक लाभ उठाता रहा है, लेकिन कालांतर में इस दुर्लभ धरोहर की अनदेखी का ही नतीजा है कि लोग तरह-तरह की बीमारियों के मकड़जाल में जकड़ते गए। वैसे तो स्वामी विवेकानंद ने भी अपने शिकागो सम्मेलन के भाषण में सम्पूर्ण विश्व को योग का संदेश दिया था लेकिन कुछ वर्षों पूर्व योग गुरु स्वामी रामदेव द्वारा योग विद्या को घर-घर तक पहुंचाने के बाद ही इसका व्यापक प्रचार-प्रसार संभव हो सका और आमजन योग की ओर आकर्षित होते गए। देखते ही देखते कई देशों में लोगों ने इसे अपनाना शुरू किया। साल 2023 में ही लगभग 190 देशों में योग दिवस के तहत 25 करोड़ से अधिक लोगों ने भाग लिया था। आज की भागदौड़ भरी जीवनशैली में योग का महत्व कई गुना बढ़ गया है। योग न केवल कई गंभीर बीमारियों से छुटकारा दिलाने में मददगार साबित होता है बल्कि मानसिक तनाव को खत्म कर आत्मिक शांति भी प्रदान करता है। दरअसल यह एक ऐसी साधना, ऐसी दवा है, जो बिना किसी लागत के शारीरिक एवं मानसिक बीमारियों का इलाज करने में सक्षम है। यह मस्तिष्क की सक्रियता बढ़ाकर दिनभर शरीर को ऊर्जावान बनाए रखता है। यही कारण है कि अब युवा एरोबिक्स व जिम छोड़कर योग अपनाने लगे हैं। माना गया है कि योग तथा प्राणायाम से जीवनभर दवाओं से भी ठीक न होने मधुमेह रोग का भी इलाज संभव है। यह वजन घटाने में भी सहायक माना गया है। योग की इन्हीं महत्ताओं को देखते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 27 सितम्बर 2014 को संयुक्त राष्ट्र महासभा से आह्वान किया था कि दुनियाभर में प्रतिवर्ष योग दिवस मनाया जाए ताकि प्रकृति प्रदत्त भारत की इस अमूल्य पद्धति का लाभ पूरी दुनिया उठा सके। यह भारत के बेहद गर्व भरी उपलब्धि रही कि संयुक्त राष्ट्र महासभा में प्रधानमंत्री के इस प्रस्ताव के महज तीन माह के भीतर 177 देशों ने अंतरराष्ट्रीय योग दिवस मनाए जाने के प्रस्ताव पर स्वीकृति की मोहर लगा दी, जिसके उपरांत संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा 11 दिसम्बर 2014 को घोषणा कर दी गई कि प्रतिवर्ष 21 जून का दिन दुनियाभर में अंतरराष्ट्रीय योग दिवस के रूप में मनाया जाएगा। अंतरराष्ट्रीय योग दिवस के लिए 21 जून का ही दिन निर्धारित किए जाने की भी खास वजह रही। दरअसल यह दिन उत्तरी गोलार्ध का पूरे कैलेंडर वर्ष का सबसे लंबा दिन होता है। इस दिन की तिथि को ग्रीष्म संक्रांति के साथ मेल खाने के लिए बनाया गया था, जो उत्तरी गोलार्ध में वर्ष का सबसे लंबा दिन होता है और प्रकाश और स्वास्थ्य का प्रतीक है। भारतीय संस्कृति के नजरिये से देखें तो ग्रीष्म संक्रांति के बाद सूर्य दक्षिणायन हो जाता है तथा यह समय आध्यात्मिक सिद्धियां प्राप्त करने में लाभकारी माना गया है। आधुनिक चिकित्सा विज्ञान भी योग के महत्व को स्वीकारने लगा है। इसलिए स्वस्थ जीवन जीने के लिए जरूरी है कि योग को अपनी दिनचर्या का अटूट हिस्सा बनाया जाए। योग केवल एक व्यायाम नहीं है बल्कि यह शरीर और मन के साथ-साथ स्वयं को सशक्त बनाने का एक बेहतरीन तरीका है। यह भारत की उस धरोहर का पुनर्जागरण है, जिसे आज पूरा विश्व अपनाकर अपने तन, मन और आत्मा को संतुलन में ला रहा है।

अभियान

जब तीन दिनों के लिए विश्राम करती हैं आदिशक्ति: कामाख्या धाम और अंबुबाची मेले का अद्भुत रहस्य

भारत को केवल मंदिरों और तीर्थों का देश नहीं कहा जाता, बल्कि यह ऐसी आध्यात्मिक भूमि है जहां आस्था, प्रकृति और रहस्य एक-दूसरे में घुल-मिल जाते हैं। यहां ऐसे अनेक तीर्थस्थल हैं जिनकी मान्यताएं सदियों से लोगों को आश्चर्यचकित करती रही हैं। इन्हीं में से एक है मां कामाख्या का पवित्र धाम, जो पूर्वोत्तर भारत के असम राज्य में स्थित है। गुवाहाटी की नीलाचल पहाड़ियों पर विराजमान यह शक्तिपीठ केवल एक मंदिर नहीं, बल्कि शक्ति साधना, तंत्र परंपरा और देवी उपासना का सबसे बड़ा केंद्र माना जाता है। हर वर्ष जून के महीने में यहां एक ऐसा धार्मिक आयोजन होता है, जिसका इंतजार लाखों श्रद्धालु और साधक पूरे वर्ष करते हैं। इस आयोजन को अंबुबाची मेला कहा जाता है।

अंबुबाची मेला केवल एक धार्मिक उत्सव नहीं है, बल्कि यह प्रकृति और नारी शक्ति के सम्मान का ऐसा प्रतीक है, जिसकी मिसाल दुनिया में बहुत कम देखने को मिलती है। इस दौरान लाखों श्रद्धालु, साधु-संत, तांत्रिक और पर्यटक कामाख्या धाम पहुंचते हैं। चारों ओर भक्ति, साधना और रहस्य का वातावरण बन जाता है। यह वह समय होता है जब मान्यता के अनुसार स्वयं मां कामाख्या रजस्वला होती हैं और इसी कारण मंदिर के कपाट तीन दिनों के लिए बंद कर दिए जाते हैं।

कामाख्या मंदिर का इतिहास अत्यंत प्राचीन और रहस्यमयी है। पुराणों के अनुसार जब राजा दक्ष ने विशाल यज्ञ का आयोजन किया और उसमें भगवान शिव का अपमान किया, तब उनकी पुत्री माता सती यह अपमान सहन नहीं कर सकीं। उन्होंने यज्ञ कुंड में अपने प्राणों की आहुति दे दी। जब भगवान शिव को यह समाचार मिला, तो वे अत्यंत क्रोधित और शोकाकुल हो उठे। उन्होंने माता सती के पार्थिव शरीर को उठाया और तांडव करने लगे। उनके तांडव से संपूर्ण सृष्टि के अस्तित्व पर संकट उत्पन्न हो गया।

तब भगवान विष्णु ने अपने सुदर्शन चक्र से माता सती के शरीर के विभिन्न अंगों को पृथक किया। जहां-जहां उनके अंग गिरे, वहां शक्तिपीठों की स्थापना हुई। मान्यता है कि नीलाचल पर्वत पर माता सती का योनिभाग गिरा था। इसी कारण यह स्थान समस्त शक्तिपीठों में अत्यंत महत्वपूर्ण माना जाता है। यहां देवी की किसी मूर्ति की पूजा नहीं होती, बल्कि एक प्राकृतिक शिला की पूजा की जाती है, जिसे देवी शक्ति का प्रत्यक्ष स्वरूप माना जाता है।

कामाख्या मंदिर की सबसे बड़ी विशेषता यही है कि यहां देवी को सृजन शक्ति और मातृत्व के प्रतीक के रूप में पूजा जाता है। भारतीय संस्कृति में नारी को सृष्टि की जननी माना गया है और कामाख्या धाम इस विचार को आध्यात्मिक रूप से स्थापित करता है। यहां देवी के उस स्वरूप की आराधना होती है जो सृष्टि के निर्माण और जीवन के निरंतर प्रवाह का आधार है।

अंबुबाची मेले का संबंध इसी सृजन शक्ति से जुड़ा हुआ है। धार्मिक मान्यता के अनुसार प्रत्येक वर्ष आषाढ़ मास में मां कामाख्या तीन दिनों तक रजस्वला होती हैं। जिस प्रकार एक स्त्री मासिक धर्म के दौरान विश्राम करती है, उसी प्रकार इन दिनों देवी को भी विश्राम दिया जाता है। मंदिर के मुख्य कपाट बंद कर दिए जाते हैं और किसी भी प्रकार की पूजा, आरती या धार्मिक अनुष्ठान नहीं किया जाता। यह परंपरा न केवल धार्मिक आस्था का प्रतीक है, बल्कि स्त्री शरीर और उसकी प्राकृतिक प्रक्रिया के सम्मान का भी संदेश देती है।

वर्ष 2026 में अंबुबाची मेले का आयोजन 22 जून से प्रारंभ होकर 26 जून तक चलेगा। इन दिनों में लाखों श्रद्धालु कामाख्या धाम पहुंचते हैं। मंदिर के कपाट बंद होने के बावजूद भक्त बड़ी श्रद्धा के साथ परिसर में उपस्थित रहते हैं और मां के पुनः दर्शन की प्रतीक्षा करते हैं। चौथे दिन विशेष शुद्धिकरण और पूजन के बाद मंदिर के द्वार श्रद्धालुओं के लिए खोल दिए जाते हैं। इस क्षण को देखने के लिए भक्तों की लंबी कतारें लग जाती हैं।

अंबुबाची मेले से जुड़ी सबसे चर्चित मान्यता उस सफेद वस्त्र की है जिसे मंदिर बंद होने से पहले गर्भगृह में रखा जाता है। कहा जाता है कि तीन दिनों के बाद जब मंदिर के कपाट खुलते हैं, तो वह वस्त्र लाल रंग का हो चुका होता है। इस वस्त्र को अत्यंत पवित्र माना जाता है और इसके छोटे-छोटे टुकड़ों को प्रसाद स्वरूप श्रद्धालुओं में वितरित किया जाता है। इसे “अंगवस्त्र” या “रक्त वस्त्र” कहा जाता है। भक्तों का विश्वास है कि यह प्रसाद मां कामाख्या के आशीर्वाद और सुरक्षा का प्रतीक है।

हालांकि इस घटना को लेकर अनेक प्रकार की धार्मिक और सांस्कृतिक व्याख्याएं की जाती हैं, लेकिन श्रद्धालुओं के लिए इसका महत्व केवल विश्वास और भक्ति से जुड़ा है। उनके लिए यह देवी की उपस्थिति और शक्ति का प्रत्यक्ष प्रमाण है। यही कारण है कि अंबुबाची मेले के दौरान प्राप्त होने वाले इस प्रसाद को अत्यंत शुभ और दुर्लभ माना जाता है।

कामाख्या धाम केवल सामान्य श्रद्धालुओं का ही केंद्र नहीं है, बल्कि यह तांत्रिक साधना का भी सबसे प्रमुख स्थान माना जाता है। अंबुबाची मेले के दौरान देश-विदेश से हजारों तांत्रिक, अघोरी, सिद्ध साधक और संन्यासी यहां एकत्रित होते हैं। इन दिनों में अनेक विशेष साधनाएं और अनुष्ठान किए जाते हैं। ऐसा माना जाता है कि यह समय आध्यात्मिक ऊर्जा के जागरण और सिद्धि प्राप्ति के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण होता है।

मंदिर परिसर में इन दिनों एक अद्भुत दृश्य देखने को मिलता है। रंग-बिरंगे वस्त्रों में साधु-संत, तपस्या में लीन तांत्रिक, मंत्रोच्चार करते श्रद्धालु और दूर-दूर से आए भक्त एक साथ दिखाई देते हैं। पूरा नीलाचल पर्वत मानो आध्यात्मिक ऊर्जा से भर उठता है। यहां आने वाला प्रत्येक व्यक्ति किसी न किसी रूप में इस अद्भुत वातावरण का अनुभव करता है। अंबुबाची मेले का एक महत्वपूर्ण संदेश यह भी है कि प्रकृति और स्त्री दोनों का सम्मान किया जाना चाहिए। भारतीय परंपरा में पृथ्वी को भी माता कहा गया है। कृषि पर आधारित समाज में यह माना जाता था कि वर्षा ऋतु के प्रारंभ में धरती भी सृजन की नई प्रक्रिया के लिए तैयार होती है। इसी कारण अंबुबाची पर्व को धरती माता और देवी शक्ति दोनों के नवसृजन काल से जोड़ा गया है। यह पर्व हमें याद दिलाता है कि जीवन का आधार सृजन है और सृजन का आधार शक्ति है।

आज के आधुनिक युग में जब विज्ञान और तकनीक तेजी से आगे बढ़ रहे हैं, तब भी कामाख्या धाम की लोकप्रियता लगातार बढ़ रही है। इसका कारण केवल धार्मिक आस्था नहीं है, बल्कि वह सांस्कृतिक और दार्शनिक संदेश भी है जो यह मंदिर देता है। यहां देवी की पूजा किसी मूर्ति के रूप में नहीं, बल्कि सृजन शक्ति के प्रतीक के रूप में की जाती है। यह विचार भारतीय दर्शन की गहराई और व्यापकता को दर्शाता है।

कामाख्या मंदिर की रहस्यमयी परंपराएं, अंबुबाची मेले की अनूठी मान्यताएं और देवी शक्ति के प्रति अटूट श्रद्धा इसे भारत के सबसे विशिष्ट तीर्थस्थलों में स्थान दिलाती हैं। हर वर्ष लाखों लोग यहां केवल दर्शन के लिए नहीं, बल्कि उस आध्यात्मिक अनुभव को महसूस करने आते हैं जो उन्हें जीवन, प्रकृति और शक्ति के वास्तविक अर्थ से परिचित कराता है। नीलाचल पर्वत पर स्थित यह पवित्र धाम आज भी करोड़ों श्रद्धालुओं की आस्था का केंद्र बना हुआ है। अंबुबाची मेले के दौरान जब मंदिर के कपाट तीन दिनों के लिए बंद होते हैं, तो यह केवल एक धार्मिक परंपरा नहीं होती, बल्कि यह उस सनातन विचार का उत्सव होता है जो नारी शक्ति को सृष्टि का मूल आधार मानता है। यही कारण है कि कामाख्या धाम को केवल एक मंदिर नहीं, बल्कि शक्ति, सृजन, प्रकृति और आध्यात्मिक चेतना का जीवंत प्रतीक माना जाता है। हर वर्ष अंबुबाची मेला इसी सत्य को पुनः स्थापित करता है कि जहां शक्ति है, वहीं सृष्टि है, और जहां सृष्टि है, वहीं जीवन का अनंत प्रवाह है।

PRGI NO. GJHIN/25/A2786 Printed, Published & Owned by RAGINI JIGNESHKUMAR VAGHELA and Printed By (1) JIGNESH RASHIKBHAI GAJJAR at Vansh Corporation, A/8, Shayona Golden Estate, Shahibag, Ahmedabad - 380 004 (2) DESAI RAHUL MAHESHBHAI at Bhavani Offset, “Bhatiya Ni Wadi, Opp Kalupur Railway Station, Kalupur, Ahmedabad-380 002. (3) HADIK MAHESHBHAI DESAI at Bhoomi Offset, “Bhatiya Ni Wadi, Opp Kalupur Railway Station, Kalupur, Ahmedabad-380 002 and Published from B/13, Sneh Plaza Shopping Center, I.O.C. Road, Chandkheda, Ahmedabad - 382 424. Editor : JIGNESHKUMAR PATHABHAI VAGHELA
Regd.Office : B/13, Sneh Plaza Shopping Center, I.O.C. Road, Chandkheda, Ahmedabad - 382 424 Gujarat,India. Phone : (o) 7698333307 (M) 8485951747,7096333307
Email:navsarjansanskruti2016@gmail.com*navsarjansanskruti2016@yahoo.com*Website : www.navsarjansanskruti.com

डांग जिला समग्र देश में ट्विन-पिट शौचालय के मामले में देश का मॉडल बना

▶▶ पूर्णतः आदिवासी जनसंख्या वाला डांग जिला ग्रामीण स्वच्छता तथा फीकल स्लज मैनेजमेंट में देश को दिखा रहा है नई राह

▶▶ डांग जिले में 95 प्रतिशत परिवारों ने ट्विन-पिट शौचालय अपनाए

▶▶ प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने वर्ष 2014 में खुले में शौचमुक्ति का लक्ष्य प्राप्त करने तथा गाँवों में ठोस व तरल कूड़ा प्रबंधन में सुधार लाने के लिए स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) की शुरुआत की थी

गांधीनगर, 20 जून : गुजरात के डांग जिले के आदिवासियों ने शायद स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) अंतर्गत ट्विन-पिट शौचालयों को लोकप्रिय बनाने वाले अक्षय कुमार और भूमि पेडनेकर के विज्ञापन नहीं देखे होंगे, लेकिन उन्होंने इस टेक्नोलॉजी को इतनी प्रभावी ढंग से अपनाया है कि आज डांग जिला ग्रामीण स्वच्छता के क्षेत्र में देश के लिए एक मॉडल बना है।

घने जंगलों, हरियाले पहाड़ों और वर्षा ऋतु के आह्लादक दृश्यों के लिए विख्यात डांग जिला आज स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) अंतर्गत फीकल स्लज मैनेजमेंट के महत्वपूर्ण घटक ट्विन-पिट शौचालयों के व्यापक स्वीकार के लिए भी पहचान प्राप्त कर रहा है।

जिला ग्रामीण विकास अभिकरण (डीआरडीए)-डांग के समन्वयक श्री विपुल परदेशी ने कहा, "डांग जिले में तीन तहसीलें और 310 गाँव हैं। डांग जिले की अनुमानित जनसंख्या 2.96 लाख है। जिले के कुल 58,966 परिवारों में से 51,613 परिवार ट्विन-पिट शौचालय अपना चुके हैं, जो जिले के कुल शौचालयों का लगभग 95 प्रतिशत है। फीकल स्लज मैनेजमेंट क्षेत्र में यह उल्लेखनीय उपलब्धि है। ये सब जन भागीदारी से संभव हुआ है। सरकार ट्विन-पिट शौचालय बनाने के लिए प्रत्येक परिवार को 12,000 रुपए की सहायता देती है।"

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने वर्ष 2014 में खुले में शौचमुक्ति का लक्ष्य प्राप्त करने और गाँवों में ठोस तथा तरल कूड़ा प्रबंधन में सुधार लाने के लिए स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) की शुरुआत की थी। उनके नेतृत्व में यह पहल स्वच्छता, महिलाओं की सुरक्षा और सर्वांगीण ग्रामीण स्वास्थ्य पर केन्द्रित एक व्यापक जन जागरण तथा व्यवहार परिवर्तन अभियान में विकसित हुई है।

मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल के नेतृत्व में राज्य सरकार ने ग्रामीण क्षेत्रों के प्रत्येक परिवार को शौचालय उपलब्ध कराने की व्यवस्था की है और स्वच्छता में देशभर में चोटी का स्थान प्राप्त किया है।

डांग जिले की सफलता ने राष्ट्रीय स्तर पर भी ध्यानाकर्षित किया

जनवरी 2026 में केन्द्रीय जल शक्ति मंत्रालय ने स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) अंतर्गत लागू किए गए विभिन्न फीकल स्लज मैनेजमेंट मॉडलों की समीक्षा के लिए राज्यों तथा केन्द्रशासित प्रदेशों के जिलों के साथ एक वर्चुअल संवाद आयोजित किया था। इस बैठक की अध्यक्षता केन्द्रीय जल शक्ति मंत्री श्री सी. आर. पाटिल ने की थी। इस बैठक के दौरान विभिन्न राज्यों ने नवीन तथा व्यापक स्तर पर लागू किए जा सकने वाले स्वच्छता मॉडल प्रस्तुत किए थे। बैठक में सुदूरवर्ती आदिवासी क्षेत्रों में ट्विन-पिट शौचालयों को बड़े पैमाने पर अपनाने के लिए गुजरात के डांग जिले को विशेष उदाहरण के रूप में प्रस्तुत किया गया था।

श्री पाटिल ने भाग लेने वाले राज्यों की प्रशंसा करते हुए कहा था, "ऐसे स्वच्छता मॉडल केवल स्वच्छ भारत के विजन को साकार करने में ही सहायक नहीं बनते, अपितु टिकाऊ कूड़ा प्रबंधन के माध्यम से रोजगार के अवसर भी सृजित करते हैं।"

ट्विन-पिट शौचालय मानव मल को सुरक्षित रूप से विघटित कर पोषक तत्वों से भरपूर जैविक खाद में परिवर्तित करता है। ग्रामीण स्वच्छता ढाँचे को मजबूत बनाने के साथ यह टेक्नोलॉजी भूमिगत जल प्रदूषण तथा असुरक्षित कूड़ा निस्तारण के जोखिम को कम करके सार्वजनिक स्वास्थ्य एवं पर्यावरण की भी रक्षा करती है।

ट्विन-पिट शौचालय कैसे काम करता है ?

ट्विन-पिट शौचालय सामान्य शौचालय की तरह ही कार्य करता है, लेकिन इसकी विशेषता यह है कि यह मानव मल को सुरक्षित जैविक खाद में परिवर्तित करता है। विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्लूएचओ) द्वारा भी इस टेक्नोलॉजी को प्रभावी तथा टिकाऊ स्वच्छता समाधान के रूप में मान्यता दी गई है।

सीवर व्यवस्था तथा सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट से जुड़े परंपरागत शौचालयों की तुलना में ट्विन-पिट शौचालय घर के स्तर पर ही कूड़े का प्रबंधन करता है। मानव मल पहले गड्ढे में जाता है, जहाँ उसका प्राकृतिक रूप से विघटन होता है। पहला गड्ढा भर जाने के बाद मल प्रवाह को दूसरे गड्ढे में मोड़ दिया जाता है। तब तक पहले गड्ढे में मौजूद मल पूरी तरह विघटित होकर सुरक्षित और पोषक तत्वों से भरपूर खाद में परिवर्तित हो जाता है, जिसे सरलता से बाहर निकालकर खाद के रूप में उपयोग में लिया जा सकता है।

इस प्रकार के शौचालय महंगी सीवर व्यवस्था की आवश्यकता को समाप्त करते हैं और भूमि एवं जल स्रोतों को प्रदूषित किए बिना कचरे का सुरक्षित प्रबंधन करते हैं।

सस्ती और टिकाऊ टेक्नोलॉजी

स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) अंतर्गत व्यक्तिगत घरेलू शौचालयों के निर्माण के लिए सरकार 12,000 रुपए की सहायता प्रदान करती है और स्थल पर ही कूड़ा प्रबंधन के लिए ट्विन-पिट टेक्नोलॉजी को सक्रिय रूप से प्रोत्साहित करती है।

ट्विन-पिट शौचालय लागत की दृष्टि से सस्ते हैं और इनमें परंपरागत फ्लश शौचालयों की तुलना में कम पानी की जरूरत पड़ती है। इसलिए ये ग्रामीण क्षेत्रों के लिए अत्यंत अनुकूल होते हैं।

इस प्रणाली में सामान्यतः लगभग तीन फीट गहराई वाले दो गोलाकार गड्ढे आस-पास बनाए जाते हैं। गड्ढों की दीवारें मधुमक्खी के छत्ते (हनीकॉम्ब पैटर्न) के आकार की बनाई जाती हैं, जिससे तरल पदार्थ आसपास की मिट्टी में आसानी से शोषित हो सके, जबकि गड्ढे के तल में कोई लाइनिंग नहीं की जाती है। सामान्यतः सीमेंट मोर्टार से युक्त ईंटों का उपयोग किया जाता है, परंतु स्थानीय स्तर पर उपलब्ध पत्थर, लकड़ी के खंभे, कंक्रीट रिंग, पकी हुई मिट्टी या पुनः उपयोग किए गए ड्रमों का भी उपयोग हो सकता है।

130 किमी की रफ्तार, लोहे जैसा हौसला: पिता के दृढ़ संकल्प से तैयार हुआ अहमदाबाद का युवा क्रिकेट स्टार प्रांजल भरवाड़!

मां की प्रार्थनाएं और पिता का संघर्ष, अब बेटा परिवार का नाम रोशन करने को तैयार! भारतीय टीम की ब्लू जर्सी पहनना ही उसका एकमात्र जुनून।

परिवार के सपनों को साकार करने का जुनूनः प्रांजल भरवाड़ के क्रिकेट करियर के पीछे पिता के त्याग की कहानी

कहते हैं कि सपने उन्हीं के सच होते हैं जिनके इरादे मजबूत होते हैं। ऐसा ही अडिग इरादा रखता है अहमदाबाद का 17 वर्षीय युवा प्रांजल भरवाड़। प्रांजल सिर्फ क्रिकेट के पीछे भागने वाला एक सामान्य युवक नहीं है, बल्कि अपने मध्यमवर्गीय परिवार की किस्मत बदलने के लिए मैदान पर दिन-रात मेहनत करने वाला एक उभरता हुआ ऑलराउंडर है। प्रांजल के परिवार की आर्थिक स्थिति ऐसी नहीं थी कि महंगी क्रिकेट अकादमी की फीस आसानी से भरी जा सके। पिता की कमाई केवल घर का खर्च चलाने तक ही सीमित थी। लेकिन बेटे की आंखों में क्रिकेट के प्रति जुनून और लगन देखकर माता-पिता ने अपने सुख-सुविधाओं के सपनों को त्याग दिया। पिता ने अपने पुराने जूते-चप्पल नहीं बदले, लेकिन बेटे के पैरों में कभी अच्छे क्रिकेट स्पाइक्स (जूते) की कमी नहीं होने दी। माता-पिता के इसी त्याग का परिणाम है कि आज प्रांजल अहमदाबाद की एक प्रसिद्ध क्रिकेट अकादमी का चमकता सितारा बन चुका है। रोज सुबह और शाम, जब शरीर जवाब देने लगता है, तब भी प्रांजल नेट्स में गेंदबाजी करना नहीं छोड़ता। इसी अथक मेहनत के दम पर वह आज 130 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से गेंद फेंकता है। उसकी इस गति के पीछे पिता का संघर्ष और मां की दुआएं जुड़ी हुई हैं।

टीम के संकटमोचक

प्रांजल सिर्फ एक तेज गेंदबाज ही नहीं, बल्कि एक बेहतरीन ऑलराउंडर भी है। जब भी टीम मुश्किल में होती है और लगातार विकेट गिर रहे होते हैं, तब प्रांजल बल्ला लेकर क्रीज पर डट जाता है और अपनी टीम को जीत की ओर ले जाने में अहम भूमिका निभाता है।

प्रांजल का अब सिर्फ एक ही सपना और एक ही जुनून है—भारतीय क्रिकेट टीम की प्रतिष्ठित ब्लू जर्सी पहनना, ताकि उसके परिवार का नाम पूरे देश में रोशन हो सके। प्रतिस्पर्धा बहुत बड़ी है और मंजिल तक पहुंचने का रास्ता कठिन है, लेकिन अपने परिवार के संघर्ष और त्याग को सफलता में बदलने का संकल्प रखने वाले इस युवा के मजबूत इरादों के सामने हर चुनौती छोटी साबित हो रही है।

नासिरनगर विध्वंस के 20 दिन बाद भी रहस्य बना हुआ है पीड़ितों पर धमकी देकर हस्ताक्षर करवाने का आरोप है

(छगनलाल मेवाड़ा द्वारा) सूरत। सूरत के नासिर नगर में 30 मई को हुई रहस्यमय तोड़फोड़ के बावजूद, जिसमें सूरत नगर निगम के अधिकारियों, पुलिस और बिल्डरों की मिलीभगत थी, अब तक कोई ठोस कारण सामने नहीं आया है और दोषियों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की गई है। इससे प्रभावित लोगों में भारी आक्रोश है। दूसरी ओर, यह बात सामने आई है कि बिल्डर के लोग, सत्ताधारी पार्टी भाजपा के कार्यकर्ताओं के साथ मिलकर, उन्हें धमका रहे हैं और परेशान कर रहे हैं ताकि दो से तीन लाख रुपये में मामला सुलझाया जा सके और उनसे कागजात पर हस्ताक्षर करवाए जा सकें। यह सारा खेल प्रभावित लोगों को मौके पर ही पीटने का एक नाटक बनता जा रहा है।

मानसून की शुरुआत में बेघर हुए इन प्रभावित लोगों की मजबूरी का फायदा उठाते हुए, बिल्डरों का समूह और कुछ प्रभावशाली लोग इस पूरे घोटाले को छिपाने में जुट गए हैं। आरोप हैं कि गरीब परिवारों को डरा-धमकाकर एक विवादित "गारंटी पत्र" पर हस्ताक्षर करने और अंगूठे के निशान लगाने के लिए

मजबूर किया जा रहा है। इन आरोपों के अनुसार, इस क्षेत्र में सक्रिय और लगातार विवादों में घिरे भाजपा के अल्पसंख्यक मोर्चे के एक स्थानीय नेता के खास लोग हाल ही में इस मामले में शामिल हुए हैं। ये दोनों व्यक्ति बिल्डर की ओर से बिचौलिए का काम कर रहे हैं और प्रभावित गरीब परिवारों को रात में धमका रहे हैं या उनके अकेलेपन का फायदा उठा रहे हैं कि अगर वे दिए गए कागजातों पर हस्ताक्षर नहीं करेंगे तो उन्हें भविष्य में एक भी रुपया नहीं मिलेगा और न ही उन्हें कोई आवास आवंटित किया जाएगा।

यह भी संदेह है कि कुछ परिवार ऐसी खुली धमकियों और लगातार मानसिक दबाव से भयभीत होकर दबाव में आकर कागजातों पर हस्ताक्षर कर चुके हैं।

वायरल हो रहे इस वचनपत्र में लिखी बातों को पढ़कर कानूनी विशेषज्ञ भी हैरान हैं। इसका कारण यह है कि इसमें लिखा है, "हम सूरत नगर निगम के टीपी रोड, नासिर नगर स्थित नगर निगम की ज़मीन पर अवैध रूप से कब्जा किए हुए थे। चूंकि यह ज़मीन हमारी संपत्ति नहीं है, इसलिए हमने खुशी-खुशी और स्वेच्छा से यह निर्माण और कब्जा हटा दिया है और ज़मीन नगर निगम को सौंप दी है।"

इस प्रकार, यह पत्र, जो वास्तविकता के बिल्कुल विपरीत है, क्योंकि लोगों के घरों को जबरन ध्वस्त कर दिया गया (जिसका वीडियो भी मौजूद है) जबकि कागजों पर इसे "स्वेच्छा से खाली" दिखाने की एक घिनौनी योजना बनाई गई है। इस तरह, पीड़ितों के सभी कानूनी अधिकारों को छीनने के लिए एक पूरी व्यवस्था स्थापित की गई है। और इसके साथ ही, यह भी लिखा गया है कि इस स्थान को खाली करने के लिए हम पर किसी व्यक्ति या संस्था द्वारा कोई दबाव नहीं डाला गया है। और हम या हमारे सास-ससुर भविष्य में इस संबंध में कोई कानूनी शिकायत या अदालती मामला दर्ज नहीं करेंगे और यदि हम ऐसा करते हैं, तो यह गारंटी पत्र स्वतः ही अमान्य माना जाएगा।

इस प्रकार, कानून के शिकंजे से बचने के लिए, निर्माणकर्ताओं से जुड़े लोग पीड़ितों के खिलाफ कानूनी हथियार तैयार कर रहे हैं और प्रभावित लोगों के गले में फंदा डालकर अपना खेल पूरा कर रहे हैं। यह ध्यान देने योग्य है कि गरीबों का रक्षक कौन है?

अयोध्या के राम मंदिर के दान में हुई लूट के मुद्दे पर AAP प्रदेश प्रवक्ता हिमांशु ठक्कर का बयान

▶▶ किसानों के खेत, छात्रों के पेपर के बाद अब मंदिर का दान भी सुरक्षित नहीं है: हिमांशु ठक्कर AAP

▶▶ अयोध्या में लूट चल रही है, तब अंग्रेजों को भी शर्म आए ऐसा कृत्य सत्ताधारी पार्टी के लोग कर रहे हैं: हिमांशु ठक्कर AAP

▶▶ सोने-चांदी की लगभग 1200 ईंटें गायब हो गई थीं, करोड़ों की लूट की रकम की चर्चा हो रही है: हिमांशु ठक्कर AAP

▶▶ मंदिर में काम करने वाले लोगों के पास एक समय साइकिल भी नहीं थी, अब दस गाड़ियां आ गई हैं: हिमांशु ठक्कर AAP

▶▶ जिन लोगों के पास फूटी कौड़ी नहीं थी, उनके पास अब करोड़ों की जमीनें कहां से आ गईं?: हिमांशु ठक्कर AAP

▶▶ दान लूटने वालों को पता है कि ऊपर तक के लोगों का आशीर्वाद उनके साथ है: हिमांशु ठक्कर AAP

▶▶ पिछले आठ महीनों के CCTV फुटेज डिलीट कर दिए गए: हिमांशु ठक्कर AAP

अहमदाबाद/गुजरातः आम आदमी पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता हिमांशु ठक्कर ने वीडियो के माध्यम से कहा कि आज तो वित्तीय खाते सुरक्षित नहीं हैं, छात्रों के पेपर सुरक्षित नहीं हैं और मंदिरों में आने वाला दान भी सुरक्षित नहीं है। पिछले एक सप्ताह से सोशल मीडिया, न्यूज चैनलों और कुछ रामभक्त धर्माचार्यों तथा संतों द्वारा जो समाचार सामने आ रहे हैं, उन्हें देखकर वास्तव में हमारा हृदय द्रवित हो उठता है। *सोने-चांदी की लगभग 1200 ईंटें गायब हो गई थीं, करोड़ों की लूट की रकम की चर्चा हो रही है। जब सोमनाथ का ताला टूटा था तब मुगल थे और जब अनेक विद्यापीठों, छोटे-बड़े मंदिरों और तीर्थस्थलों को नुकसान पहुंचाया गया था तब अंग्रेज थे। लेकिन आज जब अयोध्या में अनियमितताओं और भ्रष्टाचार के आरोप लग रहे हैं, तब मुगल या अंग्रेज नहीं बल्कि सत्ताधारी पार्टी से जुड़े लोगों के नाम सामने आ रहे हैं। यह कोई छोटी घटना नहीं है। करोड़ों रामभक्तों का हृदय वास्तव में द्रवित हो उठता है। जो लोग भगवान श्रीराम के प्रति आस्था, समर्पण भाव और भक्ति भाव से हजारों किलोमीटर की यात्रा करके दर्शन के लिए पहुंचते हैं और अपनी क्षमता के अनुसार दान करते हैं, उनके लिए ऐसे समाचार अत्यंत दुखद हैं। मीडिया में अलग-अलग प्रकार की रिपोर्टें और करोड़ों रुपये के आंकड़े सामने आ रहे हैं। ट्रस्ट से जुड़े कुछ लोगों और उनके रिश्तेदारों द्वारा अनियमितताएं किए जाने के आरोप लगाए जा रहे हैं। ऐसे लोग, जिनके पास कभी साइकिल खरीदने के भी पैसे नहीं थे, वे आज कई गाड़ियों के मालिक बन गए हैं। जिनके पास एक दुकान भी नहीं थी, वे बड़ी-बड़ी इमारतों के मालिक बन गए हैं। जिनके पास कुछ भी नहीं था, वे करोड़ों की जमीनों के मालिक बन गए हैं। पूरी व्यवस्था कैसे काम करती है, इसे समझने की जरूरत है। इस प्रकार की घटनाएं बार-बार क्यों हो रही हैं, इस पर हर रामभक्त को विचार करना होगा। इन लोगों को भगवान श्रीराम का भी डर नहीं है और सत्ता में बैठे शासकों का भी डर नहीं है। क्योंकि उन्हें लगता है कि ऊपर तक उनका आशीर्वाद है और उनका कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता। कोई छोटा-मोटा कर्मचारी निलंबित हो जाएगा, कोई जांच समिति या SIT का गठन हो जाएगा, लेकिन ऊपर से नीचे तक यदि जवाबदेही तय नहीं होगी तो ऐसी घटनाएं फिर होती रहेंगी। मजे की बात तो यह है कि ऐसे समाचार भी सामने आए हैं कि पिछले आठ महीनों के CCTV फुटेज डिलीट या डिस्टर्ब कर दिए गए हैं। AAP प्रवक्ता हिमांशु ठक्कर ने आगे कहा कि इतनी बड़ी घटना में CCTV की पूरी रिकॉर्डिंग गायब हो जाए, तो क्या किसी के सहयोग के बिना यह संभव है? कुछ समय तक यह मुद्दा चर्चा में रहेगा, फिर धीरे-धीरे सब शांत हो जाएगा। लेकिन सबसे बड़ा दुख तो रामभक्तों की भावनाओं के साथ हुआ खिलवाड़ है। हाल ही में ऐसे समाचार भी आए हैं कि दान में उल्लेखनीय कमी आई है। लेकिन सवाल यह है कि सच्चा दान क्या है? दान की पवित्रता कैसे बनाए रखी जा सकती है? शिक्षा और स्वास्थ्य जैसे क्षेत्रों में करोड़ों रुपये का दान उपयोग किया जाए तो उसका लाभ समाज को मिलता है। किसी गरीब बच्चे की स्कूल या कॉलेज की फीस भर दी जाए, किसी जरूरतमंद को उपचार मिल जाए, तो शायद भगवान श्रीराम अधिक प्रसन्न होंगे। मैं सभी रामभक्तों से अनुरोध करता हूं कि इस देश की संस्कृति हमारी संस्कृति है। यदि मंदिरों में आने वाला दान भी सुरक्षित न रहे, तो लोगों की आस्था पर असर पड़ता है। मंदिरों में बढ़ते VIP कल्चर और ऐसी घटनाओं पर सामूहिक रूप से विचार करने की आवश्यकता है। सरकार के पास अपने संसाधनों की सुरक्षा करने की भी क्षमता नहीं है। कई बार सरकारी तंत्र की लापरवाही के मामले सामने आते हैं। तो फिर मंदिरों के प्रबंधन में सरकार की भूमिका कितनी और कैसी होनी चाहिए, इस पर भी चर्चा होनी चाहिए। इस देश में अनेक मठ, पीठ, संत और शंकराचार्य परंपराएं हैं। क्या सनातन परंपरा के अग्रणियों के साथ बैठकर ऐसी व्यवस्था नहीं बनाई जा सकती कि मंदिरों में एक निश्चित राशि से अधिक आय होने पर उसका एक हिस्सा शिक्षा, स्वास्थ्य और स्थानीय विकास के लिए उपयोग किया जाए? समय आ गया है कि हम इन मुद्दों पर गंभीरता से विचार करें। भगवान श्रीराम सभी को सद्बुद्धि दें। "वसुधैव कुटुम्बकम्" और "विद्या धनं सर्वधन प्रधानम्" जैसे हमारी संस्कृति के मूल्यों को फिर से जीवंत करने की आवश्यकता है। आज स्थिति ऐसी बन गई है कि लोग मंदिरों के दान पर भी सवाल उठाने लगे हैं। इस दुर्भाग्यपूर्ण मानसिकता और परिस्थिति पर निश्चित रूप से विचार करना होगा।

डॉल्फिन संरक्षण में गुजरात का योगदान महत्वपूर्ण

राज्य के समुद्र तटीय क्षेत्र में लगभग 680 से अधिक डॉल्फिन की उपस्थिति : वन एवं पर्यावरण मंत्री श्री अर्जुन मोढवाडिया

प्रसिद्ध शिवराजपुर तथा पोशित्रा डॉल्फिन साइट के लिए 'बेस्ट स्पॉट'

अन्य महत्वपूर्ण तथ्य

- ▶▶ डॉल्फिन का शिकार या उसे नुकसान पहुँचाना गैर-जमानती अपराध
- ▶▶ 'स्वस्थ इकोसिस्टम' के लिए डॉल्फिन बहुत ही महत्वपूर्ण जलचर प्राणी
- ▶▶ कच्छ की खाड़ी में स्थित भारत का प्रथम समुद्री राष्ट्रीय उद्यान डॉल्फिन का मुख्य घर
- ▶▶ 'मानव मित्र जलचर' के रूप में पहचानी जाने वाली डॉल्फिन देश-विदेश के पर्यटकों के लिए नया आकर्षण

गांधीनग : वन एवं पर्यावरण मंत्री श्री अर्जुन मोढवाडिया ने कहा है कि वन्यजीवों के साथ-साथ सबसे सुंदर एवं आकर्षक जलचर जीव 'डॉल्फिन' के संरक्षण-संवर्धन में गुजरात ने महत्वपूर्ण योगदान दिया है। मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल के मार्गदर्शन में जलचर एवं वन्यजीव संरक्षण तथा संवर्धन के विशेष प्रयासों के परिणामस्वरूप वर्ष 2025 की अंतिम गणना के अनुसार गुजरात के 4,087 वर्ग किलोमीटर में फैले समुद्री क्षेत्र में लगभग 680 से अधिक डॉल्फिन दर्ज हुई हैं। वहीं जलचर एवं वन्यजीव पर्यटन क्षेत्र में भी गुजरात ने लंबी छलांग लगाई है। गुजरात के प्रसिद्ध पर्यटन स्थलों शिवराजपुर तथा पोशित्रा का समुद्र तट डॉल्फिन के लिए 'बेस्ट स्पॉट' के रूप में भी जाना जाता है। यहाँ पानी बहुत ही स्वच्छ होने के कारण डॉल्फिन सरलता से दिखाई दे जाती हैं।

श्री मोढवाडिया ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के सीधे मार्गदर्शन में गुजरात में वन विभाग ने पिछले 12 वर्षों में समुद्र तट पर मैंग्रोव के साथ-साथ जलचर जीवों के संरक्षण तथा उनके आवास-विकास के लिए अनेक प्रकार के संयुक्त प्रयास शुरू किए हैं। कच्छ की खाड़ी के दक्षिणी भाग में स्थित मरीन नेशनल पार्क तथा मरीन सैंक्चुरी के ओखा से नवलखी तक फैले 1,384 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में सर्वाधिक 498 डॉल्फिन होने की संभावना है, जबकि कच्छ की खाड़ी के उत्तरी भाग में कच्छ वृत्त अंतर्गत 1,821 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में 168, भावनगर के 494 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में 10 तथा मोरबी के 388 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में 4 डॉल्फिन देखी गई हैं। इस प्रकार; कच्छ की खाड़ी में स्थित भारत का यह प्रथम समुद्री राष्ट्रीय उद्यान डॉल्फिन का मुख्य घर है।

उन्होंने कहा, "स्वस्थ इकोसिस्टम के लिए डॉल्फिन बहुत ही महत्वपूर्ण जलचर प्राणी है। समुद्री स्तनधारी प्राणियों के कुछ शीर्ष शिकारी खाद्य श्रृंखला में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं और समुद्री इकोसिस्टम में संतुलन सुनिश्चित करने में भी सहायता करते हैं। इन डॉल्फिनों को बचाने में कच्छ से भावनगर तक समुद्र में मछली पकड़ने का कार्य करने वाले मछुआरे भाइयों का योगदान भी उतना ही महत्वपूर्ण है। इन सर्वग्राही प्रयासों के परिणामस्वरूप गुजरात के समुद्र तट पर दिखाई देने वाली डॉल्फिन देश-विदेश के पर्यटकों के लिए नया आकर्षण केन्द्र बनी हैं।"

उन्होंने जोड़ा कि डॉल्फिन लुप्तप्राय प्रजातियों में शामिल होने के कारण उनका शिकार करना या उन्हें नुकसान पहुँचाना गैर-जमानती अपराध है।

गुजरात में दिखाई देने वालीं डॉल्फिन की विशेषताएँ

गुजरात के समुद्री क्षेत्र में मुख्यतः इंडो-पैसिफिक हम्पबैक डॉल्फिन तथा बॉटलनोज डॉल्फिन; इन दो प्रकार की डॉल्फिन सबसे अधिक दिखाई देती हैं। हम्पबैक डॉल्फिन अधिकतर अरब सागर में पाई जाती हैं। इसे इसकी विशिष्ट कूबड़ और विस्तारित डॉर्सल फिन अर्थात् पूँछ से पहचाना जा सकता है। डॉल्फिन अपने मैत्रीपूर्ण एवं जिज्ञासु स्वभाव के लिए जानी जाती है। डॉल्फिन कई बार लहरों में उछलती-कूदती और खेलती हुई दिखाई देती है, जो पर्यटकों को अपने एक्रोबैटिक प्रदर्शन से आनंदित कर देती है। इसका शरीर आकर्षक तथा इसके मुँह का आकार 'बोतल' जैसा होने के कारण इसे आसानी से पहचाना जा सकता है। डॉल्फिन का मुख्य भोजन मछलियाँ, केकड़े और झींगे होने के कारण यह समुद्र तटों और नदीमुखों के पास दिखाई देती है। हम्पबैक डॉल्फिन सामान्यतः 2.5 से 3.2 मीटर लंबी होती है और इसका वजन 150 से 250 किलोग्राम तक हो सकता है।

इसके अतिरिक्त; मछलियों की तरह डॉल्फिन के गलफड़े नहीं होते हैं। वह स्तनधारी प्राणी होने के कारण फेफड़ों से श्वास लेती है। इसलिए वह हर कुछ मिनट में पानी की सतह पर सिर बाहर निकालकर साँस लेने के लिए आती है। यह दृश्य पर्यटकों के लिए रोमांचक अनुभव बन जाता है।

यहाँ उल्लेखनीय है कि भारत का राष्ट्रीय जलचर प्राणी 'गंगा डॉल्फिन' है, जो पवित्र गंगा नदी की शुद्धता दर्शाता है। भारत सरकार ने 5 अक्टूबर 2009 को डॉल्फिन को भारत का 'राष्ट्रीय जलचर प्राणी' घोषित किया था। साथ ही; डॉल्फिन 'मानव मित्र जलचर प्राणी' के रूप में जानी जाती है तथा अपने बौद्धिक-मनोरंजक स्वभाव के लिए लोकप्रिय है। कच्छ से भावनगर तक के समुद्री तटों पर डॉल्फिन को देखना अपार आनंद के साथ रोमांचक अनुभव प्रदान करता है, जो गुजरात सहित देश-विदेश के पर्यटकों के लिए विशेष आकर्षण का केन्द्र बन रहा है।

भाजपा की प्राथमिकता स्कूल-अस्पताल नहीं बल्कि फाइव स्टार कमलम बनाने की है: मनोज सोरठिया, प्रदेश संगठन महामंत्री AAP

▶▶ भाजपा का कमलम गुजरात में हुई लूट और गुलामी का प्रतीक है: मनोज सोरठिया

▶▶ 5 वर्षों में भाजपा ने 100 करोड़ के कमलम बनाए: मनोज सोरठिया

▶▶ अब लोग ही सवाल पूछ रहे हैं कि 30 वर्षों में गुजरात के लोगों का क्या विकास हुआ?: मनोज सोरठिया

▶▶ 30 वर्षों में गुजरात के लोगों को अच्छी शिक्षा और स्वास्थ्य व्यवस्था मिली?: मनोज सोरठिया

▶▶ 30 वर्षों के शासन के बाद गुजरात के किसानों को पर्याप्त भाव और पर्याप्त खाद मिलती है?: मनोज सोरठिया

▶▶ 30 वर्षों के शासन में गुजरात के लोग पायमाल हुए हैं: मनोज सोरठिया

अहमदाबाद/सूरत/गुजरातः आम आदमी पार्टी के प्रदेश संगठन महामंत्री मनोज सोरठिया ने वीडियो के माध्यम से कहा कि आज भाजपा के 30 वर्षों के शासन के बाद गुजरात के लोग एक सवाल पूछ रहे हैं कि क्या इन 30 वर्षों में गुजरात के लोगों का विकास हुआ है? क्या गुजरात के लोगों के लिए शिक्षा व्यवस्था फाइव स्टार स्तर की बनी है? क्या गुजरात के लोगों को अच्छे सरकारी अस्पताल और अच्छी स्वास्थ्य सुविधाएं मिलती हैं? क्या गुजरात का किसान समृद्ध हुआ है? क्या गुजरात के किसानों को अपनी फसल का उचित मूल्य मिलता है? क्या उन्हें पर्याप्त खाद मिलती है? उनकी आजीविका के लिए सरकार ने इन 30 वर्षों में क्या किया है? क्या गुजरात का छोटा व्यापारी आज की परिस्थिति में अपना रोजगार-धंधा अच्छी तरह चला सकता है? क्या इन 30 वर्षों में गुजरात के लोग लाभ में रहे हैं? आज गुजरात के प्रत्येक व्यक्ति पर ऋण और किस्तें चुकाने का दबाव है। सभी मकान, सभी गाड़ियां और सभी छोटे-बड़े व्यवसाय आज ऋण पर चल रहे हैं। ऐसे समय में भारतीय जनता पार्टी की प्राथमिकता देखिए।

'आप' नेता मनोज सोरठिया ने आगे कहा कि भाजपा की प्राथमिकता अपने फाइव स्टार कमलम बनाने की है। यह कमलम आज गुजरात को गौरव की ओर नहीं बल्कि गुलामी की ओर धकेल रहा है। भारतीय जनता पार्टी ने पिछले 30 वर्षों में गुजरात को लूटकर अपनी बादशाहत स्थापित की है। मानो अपना फरमान चला रही हो और लोगों से कह रही हो कि हमने तुम्हें गुलाम बना दिया है। आज गुजरात की ऐसी स्थिति है। पिछले पांच वर्षों में भाजपा ने 100 करोड़ रुपये से अधिक खर्च करके बड़े फाइव स्टार कार्यालय बनाए हैं। भाजपा अपने संगठन को मजबूत करने और अपनी जड़ों को मजबूत करने के लिए करोड़ों रुपये खर्च करती है, लेकिन लोगों की सुख-सुविधा के लिए, लोगों के कल्याण के लिए और लोगों की मूलभूत आवश्यकताओं के लिए कोई काम नहीं किया है। आज मैं गुजरात की जनता से अनुरोध करता हूं कि अब इस भाजपा को पहचानने की जरूरत है। यह भाजपा आधुनिक तानाशाह है। तानाशाहों से भी अधिक बुरी तरह गुजरात की जनता का शोषण करने वाले लोग भारतीय जनता पार्टी में बैठे हैं। गुजरात की जनता से मेरी विनती है कि भाजपा के दुष्कर्मों को पहचानिए, भाजपा की लूट को पहचानिए और भाजपा ने हमें जिस गुलामी की ओर धकेला है, उस गुलामी को पहचानिए।

अब 8000 से अधिक जीएसआरटीसी बसों में क्यूआर कोड पर आधारित फीडबैक सिस्टम लागू, यात्रियों से मिला शानदार फीडबैक

▸▸ जीएसआरटीसी को यात्रियों से मिली जोरदार प्रतिक्रिया, औसत रेटिंग 4.7 स्टार तक पहुंचा

▸▸ मार्च से जून 2026 के दौरान 3.13 लाख से अधिक यात्रियों की फीडबैक रिपोर्ट मिली

▸▸ उप मुख्यमंत्री श्री हर्ष संघवी के नेतृत्व में गुजरात की सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था में उल्लेखनीय परिवर्तन आया, जिसमें यात्रियों की सुविधा, सुरक्षा और सेवा को केंद्र में रखा गया है

गांधीनगर : गुजरात राज्य सड़क परिवहन निगम (जीएसआरटीसी) ने मार्च 2025 में ट्रायल आधार पर क्यूआर-कोड आधारित यात्री फीडबैक सिस्टम शुरू किया था, जिसे अब राज्यभर में बड़े पैमाने पर लागू किया जा रहा है। इस पहल को लाखों यात्रियों का उत्साहजनक फीडबैक मिला है, और 5 में से 4.7 स्टार की औसत संतोषजनक रेटिंग मिली है।

उप मुख्यमंत्री श्री हर्ष संघवी के मार्गदर्शन में राज्य की सार्वजनिक परिवहन सेवाओं में व्यापक सुधार किए गए हैं, जिनमें यात्रियों की सुविधा, सुरक्षा और सेवा की गुणवत्ता को सर्वोच्च प्राथमिकता दी गई है।

राज्य संचालित बस सेवाओं में यात्रियों को अधिक सुरक्षित, आरामदायक और गुणवत्तापूर्ण यात्रा का अनुभव देने के उद्देश्य से यह फीडबैक सिस्टम शुरू किया था। यात्री अपनी यात्रा के दौरान क्यूआर कोड को स्कैन करके सीधे अपने मोबाइल फोन के जरिए फीडबैक दे सकते हैं। यात्री किसी भी सेवा को लेकर अपनी शिकायत भी बता सकते हैं।

शुरुआत में इस डिजिटल व्यवस्था को केवल प्रीमियम लग्जरी बसों में लागू किया गया था। लेकिन, इसे अच्छी प्रतिक्रिया मिलने पर अब जीएसआरटीसी ने इसे व्यापक स्तर पर लागू किया है। आज, राज्य के 125 बस स्टेशन, डिपो कंट्रोल पॉइंट्स तथा 8000 से अधिक बसों में क्यूआर कोड लग चुके हैं।

इस सिस्टम के जरिए प्राप्त प्रतिक्रिया के अनुसार यात्रियों ने जीएसआरटीसी की सेवाओं पर बहुत अधिक संतुष्टि जाहिर की है। पांच स्टार के मापदंड पर दी गई रेटिंग्स दिखाती है कि यात्री सेवा के विभिन्न मानदंडों को लेकर खुश हैं और निगम की ओर से यात्रा के अनुभव को और भी बेहतर बनाने के लिए किए गए प्रयासों को सकारात्मक प्रतिक्रिया मिली है। जीएसआरटीसी की 1 मार्च से 19 जून, 2026 तक की पैसेंजर फीडबैक रिपोर्ट के अनुसार निगम ने 5 में से 4.7 स्टार की मजबूत यात्री संतुष्टि रेटिंग प्राप्त की है। यह रिपोर्ट 3,13,824 यात्रियों से प्राप्त फीडबैक पर आधारित है, जो दिखाती है कि यात्री विभिन्न कामकाज के पैमानों पर निगम की सेवाओं के प्रति बहुत अधिक संतुष्ट हैं।

सुझावों और शिकायतों पर त्वरित कार्रवाई

उप मुख्यमंत्री श्री हर्ष संघवी ने कहा, "जीएसआरटीसी केवल फीडबैक एकत्र नहीं करता, बल्कि उसके आधार पर सक्रिय रूप से कार्रवाई भी करता है। यात्रियों द्वारा भेजी जाने वाली शिकायतों, सुझावों और मुद्दों को तत्काल संबंधित विभागों और स्थानीय बस डिपो तक पहुंचाया जाता है। प्राप्त प्रतिक्रिया की अविलंब जांच की जाती है और आवश्यक सुधारात्मक कदम स्थल पर ही उठाए जाते हैं। हम यात्रियों को बेहतरीन बेहतरीन सार्वजनिक परिवहन सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए कृतसंकल्प हैं।"

जीएसआरटीसी के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि यात्रियों का फीडबैक निगम की सतत प्रगति के लिए एक महत्वपूर्ण साधन है और निगम पूरे गुजरात में सुरक्षित, विश्वसनीय और यात्री-अनुकूल परिवहन सेवाएं प्रदान करे के लिए प्रतिबद्ध है। **सभी सेवाओं के लिए ऊंची रेटिंग्स** यात्री अपनी यात्रा के विभिन्न पहलुओं पर 1 से 5 स्टार के पैमाने पर रेटिंग देते हैं। औसत स्कोर दिखाता है कि यात्री निगम के कामकाज से काफी संतुष्ट है। विभिन्न मानदंडों पर निगम को मिली रेटिंग्स पर नजर डालें, तो स्टाफ के व्यवहार पर निगम को 5 में से 4.9 स्टार रेटिंग मिली है। वहीं, यात्रियों की सुरक्षा के मुद्दे पर 5 में से 4.9 स्टार, स्वच्छता पर 5 में से 4.8 स्टार, बैठने की सुविधा पर 5 में से 4.8 स्टार तथा समय पालन पर 5 में से 4.8 स्टार मिले हैं।

खान सर को कोर्ट से बड़ी राहत, 25 जून तक गिरफ्तारी पर रोक; अगली सुनवाई पर टिकीं सबकी निगाहें

पटना। बिहार के चर्चित शिक्षक, यूट्यूबर और लाखों छात्रों के बीच लोकप्रिय नाम फैजल खान उर्फ खान सर को पटना सिविल कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। कोचिंग विवाद से जुड़े मामले में अदालत ने उनकी गिरफ्तारी पर लगी अंतरिम रोक को 25 जून तक बढ़ा दिया है। इस फैसले के बाद फिलहाल खान सर को तत्काल गिरफ्तारी या किसी प्रकार की दंडात्मक कार्रवाई का सामना नहीं करना पड़ेगा। अदालत के इस आदेश ने न केवल खान सर बल्कि उनके समर्थकों और छात्रों के बीच भी राहत की भावना पैदा कर दी है, जो पिछले कुछ दिनों से इस मामले की हर सुनवाई पर नजर बनाए हुए थे। शनिवार को हुई सुनवाई के दौरान अदालत में मामले से संबंधित महत्वपूर्ण दस्तावेज प्रस्तुत किए गए। न्यायालय के निर्देश के अनुसार पुलिस ने केस डायरी अदालत में जमा की, जिसके बाद पूरे मामले पर विस्तृत चर्चा हुई। अदालत ने स्पष्ट किया कि वह मामले से जुड़े सभी तथ्यों, दस्तावेजों और पुलिस द्वारा प्रस्तुत सामग्री का गहन अध्ययन करने के बाद ही कोई अंतिम निर्णय लेगी। इसी कारण अगली सुनवाई तक यथास्थिति बनाए रखने का आदेश दिया गया है। न्यायालय ने अपने आदेश में कहा कि जब तक मामले की पूरी समीक्षा नहीं हो जाती, तब तक खान सर के खिलाफ कोई भी कठोर, बलपूर्वक या दंडात्मक कार्रवाई नहीं की जाएगी। इस आदेश को कानूनी रूप से महत्वपूर्ण माना जा रहा है क्योंकि इससे जांच एजेंसियों को भी स्पष्ट संकेत मिला है कि अगली सुनवाई तक किसी प्रकार की गिरफ्तारी या दबावपूर्ण कार्रवाई से बचना होगा। खान सर के साथ-साथ इस मामले में उनके तीन स्टाफ सदस्यों को भी अदालत से राहत मिली है। न्यायालय ने उनके खिलाफ भी फिलहाल किसी प्रकार की कठोर कार्रवाई पर रोक लगा दी है। इससे यह साफ हो गया है कि अदालत मामले के सभी पक्षों को सुनने और उपलब्ध साक्ष्यों का परीक्षण करने के बाद ही आगे की दिशा तय करना चाहती है। पिछले कुछ समय से यह मामला लगातार चर्चा में बना हुआ है। खान सर का नाम बिहार ही नहीं बल्कि पूरे देश में शिक्षा के क्षेत्र में एक लोकप्रिय व्यक्तित्व के रूप में जाना जाता है।

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने पश्चिम बंगाल के तारकेश्वर-हुगली से 'प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना' की 23वीं किस्त जारी की

▸▸ 23वीं किस्त के तहत गुजरात के 51.28 लाख धरतीपुत्रों को 1025 करोड़ रुपए की सहायता मिली

▸▸ मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल की अध्यक्षता में गांधीनगर में राज्य स्तरीय 'पीएम किसान उत्सव दिवस' मनाया गया

▸▸ कृषि मंत्री श्री जीतूभाई वाघाणी और राज्य मंत्री श्री रमेशभाई कटारा की प्रेरक उपस्थिति

▸▸ सरकार किसानों की आय बढ़ाने, खेती को अधिक समृद्ध करने और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने की दिशा में निरंतर कार्यरत है : मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल

▸▸ 2019 से शुरू हुई पीएम किसान योजना किसानों के लिए बीज, खाद और दवा सहित दूसरी आवश्यकताओं के लिए बड़ा आर्थिक सहारा बनी है : कृषि मंत्री श्री जीतूभाई वाघाणी

▸▸ महानुभावों के करकमलों से किसानों को विभिन्न कृषि संबंधित योजनाओं की सहायता वितरित की गई

▸▸ राज्यभर के किसानों ने प्रधानमंत्री के संबोधन का सीधा प्रसारण देखा

गांधीनगर : प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने शनिवार को पश्चिम बंगाल के हुगली जिले के तारकेश्वर से 'प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना' की 23वीं किस्त जारी की। इस किस्त के तहत देश के 9.44 करोड़ किसानों के बैंक खातों में कुल 18,880 करोड़ रुपए से अधिक की सहायता राशि भेजी गई।

वहीं, 'पीएम किसान सम्मान निधि योजना' के अंतर्गत गुजरात के 51.28 लाख किसानों को 1025 करोड़ रुपए से अधिक सहायता प्राप्त हुई।

इस उद्देश्य से, गांधीनगर में मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल की अध्यक्षता में राज्य स्तरीय 'पीएम किसान उत्सव दिवस' कार्यक्रम आयोजित किया गया। कृषि मंत्री श्री जीतूभाई वाघाणी और राज्य मंत्री श्री रमेशभाई कटारा भी इस कार्यक्रम में मौजूद रहे।

मुख्यमंत्री ने इस मौके पर लाभार्थी किसानों को कृषि और बागवानी की विभिन्न खेती संबंधित योजनाओं की सहायता का वितरण किया। महानुभावों सहित राज्य के हजारों किसानों ने प्रधानमंत्री के संबोधन का सीधा प्रसारण देखा।

मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल ने इस अवसर पर कहा कि सरकार किसानों की आय बढ़ाने, खेती को अधिक समृद्ध करने और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने की दिशा में लगातार काम कर रही है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार किसानों की समृद्धि, पानी का संरक्षण, प्राकृतिक खेती और आधुनिक कृषि व्यवस्था के जरिए गुजरात को कृषि क्षेत्र में और भी मजबूत बनाने के लिए कृतसंकल्प है। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में सुशासन के 12 वर्ष पूरे हो गए हैं। इन 12 वर्षों में किसानों के हित को केंद्र में रखकर अनेक ऐतिहासिक निर्णय और जनकल्याणकारी योजनाएं लागू की गई हैं। राज्य सरकार ने भी किसानों के कल्याण को केंद्र में रखकर खेती को और अधिक आत्मनिर्भर, टिकाऊ और समृद्ध बनाने के अनेक सफल प्रयास किए हैं।

उन्होंने कहा कि पानी किसानों की सबसे बड़ी आवश्यकता है। गुजरात को इस बात का अनुभव है कि कैसे बिना पानी के खेती की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। पहले खेती मुख्यतः वर्षा पर निर्भर होती थी, लेकिन आज नर्मदा आधारित सिंचाई व्यवस्था और नहरों के विस्तार के आयोजन से अनेक क्षेत्रों में किसान अधिक उत्पादन हासिल कर रहे हैं और तीनों सीजन में फसल ले रहे हैं।

मुख्यमंत्री ने कम वर्षा की स्थिति में योजनाबद्ध खेती के लिए आह्वान करते हुए कहा कि इस वर्ष अल नीनो के प्रभाव के कारण बरसात के सामान्य से कम होने की संभावना व्यक्त की गई है। बदलते मौसम की स्थिति में किसानों को घबराने की जरूरत नहीं है, अलबत्ता वैज्ञानिक दृष्टिकोण के साथ कम पानी की जरूरत वाली फसलें और उचित बीज का चुनाव करके योजनाबद्ध खेती करने पर बल दिया गया है।

उन्होंने कहा कि किसानों को सिंचाई के लिए अधिक सुविधा उपलब्ध कराने के लिए सरकार ने नर्मदा के पानी का उचित उपयोग करके तालाबों और बांधों में जल संग्रहण करने की काम भी शुरू कर दिया है।

उन्होंने किसानों के लिए राज्य सरकार के महत्वपूर्ण निर्णय का जिक्र करते हुए कहा कि नर्मदा कमांड एरिया के आसपास के तालाबों को भरने की सीमा को 3 किलोमीटर से बढ़ाकर 7 किलोमीटर कर दिया गया है।

मुख्यमंत्री ने छोटे किसानों को लाभ पहुंचाने वाले निर्णय के बारे में कहा कि किसानों की फसलों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए तारबंदी (वायर फेंसिंग) योजना के तहत महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया है। पहले, इस योजना की पात्रता के लिए पांच हेक्टेयर की सीमा थी, लेकिन छोटे और सीमांत किसानों को भी योजना का लाभ पहुंचाने के लिए इस सीमा को घटाकर अब 1 हेक्टेयर तक कर दिया गया है। साथ ही, किसान उचित समय और उचित दाम पर अपनी उपज बेच सकें, इसके लिए खेत उत्पादों को सुरक्षित रखने के लिए भंडारण सुविधाएं बढ़ाने पर भी जोर दिया गया है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि खेती के साथ-साथ जमीन की सेहत भी बनी रहे, इसके लिए 'खेत बचाओ अभियान' के तहत विभिन्न प्रयास किए जा रहे हैं। स्वस्थ जमीन से गुणवत्ता युक्त फसल मिलती है और मानव स्वास्थ्य पर भी सकारात्मक प्रभाव पड़ता है।

मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल ने प्राकृतिक कृषि को किसानों के लिए एक नया अवसर बताते हुए कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के मार्गदर्शन में देशभर में प्राकृतिक खेती का अभियान आगे बढ़ रहा है। जमीन की नैसर्गिक शक्ति (उर्वरता) को बनाए रखने के लिए राज्य सरकार प्राकृतिक खेती को बढ़ावा दे रही है। उन्होंने इस बात का भी उल्लेख किया कि राज्यपाल श्री आचार्य देवव्रत जी भी गांव-गांव जाकर किसानों को प्राकृतिक खेती की तकनीक और उसके लाभों के संबंध में मार्गदर्शन दे रहे हैं। मुख्यमंत्री ने जल संरक्षण के लिए अमृत सरोवर और 'कैच द रेन' अभियान के बारे में कहा कि गुजरात ने हर जिले में 75 अमृत सरोवर बनाने के लक्ष्य की तुलना में अधिक सरोवरों का निर्माण किया है। इस अभियान के तहत बरसाती पानी को भूमि में उतारकर भूमिगत जलस्तर को ऊंचा उठाने के प्रयास हो रहे हैं। इसके लिए प्रत्येक विधायक को 50 लाख रुपए आवंटित करके बोर की रिचार्जिंग सहित जल संरक्षण के कार्यों को बढ़ावा दिया जा रहा है।

कृषि मंत्री श्री जीतूभाई वाघाणी ने कहा कि बिना किसी बिचौलिए के पूरी पारदर्शिता के साथ आज गुजरात के 51 लाख से अधिक किसानों के बैंक खातों में 1025 करोड़ रुपए से अधिक की राशि सीधे हस्तांतरित हुई है। अब तक, देश के 11 करोड़ से अधिक किसानों के खातों में 4.50 लाख करोड़ रुपए की सहायता भेजी गई है। वर्ष 2019 से शुरू हुई यह योजना किसानों के लिए बीज, खाद और कीटनाशक दवा जैसी जरूरतों के लिए बड़ा आर्थिक सहारा बन गई है। इसके अलावा, सरकार विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं और समर्थन मूल्य पर खरीद के जरिए ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत बना रही है।

मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल के संवेदनशील नेतृत्व की सराहना करते हुए कृषि मंत्री ने आगे कहा कि राज्य सरकार ने किसानों के हित में अनेक ऐतिहासिक निर्णय लिए हैं, जिनमें कृषि यंत्रीकरण के लिए हजारों करोड़ रुपए की सब्सिडी से लेकर प्राकृतिक आपदा के समय ऐतिहासिक 11,000 करोड़ रुपए के राहत पैकेज की घोषणा शामिल है। संकट के समय नर्मदा का पानी छोड़कर ताबालों और बांधों को भरने जैसे निर्णयों से गुजरात के किसान सुखी और समृद्ध बने हैं।

कार्यक्रम की शुरुआत में कृषि और किसान कल्याण विभाग के प्रधान सचिव श्री आर.सी. मीणा ने स्वागत भाषण में कार्यक्रम की रूपरेखा दी

कार्यक्रम में जिला पंचायत अध्यक्ष श्री राजेशभाई पटेल, गांधीनगर उत्तर की विधायक श्रीमती रीटाबेन पटेल, गुजरात एग्रो इंडस्ट्रीज कॉर्पोरेशन के प्रबंध निदेशक श्री विजय खराड़ी, गांधीनगर कलेक्टर श्री रवीन्द्र खताले, गांधीनगर जिला विकास अधिकारी श्री हसरत जैस्मिन सहित कृषि विभाग के अधिकारी, कर्मचारी और बड़ी संख्या में किसान उपस्थित रहे।

मंडल रेल प्रबंधक श्री राजू भडके ने वडोदरा यार्ड रीमॉडलिंग का किया निरीक्षण

हाई स्पीड रेल स्टेशन को जोड़ेगा नया प्लेटफार्म, 22 डिब्बों की ट्रेनों के लिए प्लेटफार्म 4 & 5 का हो रहा विस्तार

पश्चिम रेलवे के वडोदरा मंडल के मंडल रेल प्रबंधक श्री राजू भडके के नेतृत्व में वडोदरा स्टेशन पर व्यापक यार्ड रीमॉडलिंग एवं ट्रैक इंफ्रास्ट्रक्चर के आधुनिकीकरण का कार्य प्रगति पर है। मंडल रेल प्रबंधक श्री राजू भडके ने वडोदरा स्टेशन का दौरा कर इंफ्रा के इस महत्वपूर्ण कार्य का वरिष्ठ अधिकारिओं के साथ निरीक्षण किया।

श्री भडके ने बताया कि इस महत्वाकांक्षी परियोजना का उद्देश्य परिचालन संरक्षा में वृद्धि, लाइन एवं प्लेटफॉर्म क्षमता का विस्तार, ट्रेन संचालन दक्षता में सुधार तथा यात्रियों को बेहतर सुविधाएं प्रदान करना है। साथ ही, भविष्य की परिवहन आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए स्टेशन के बुनियादी ढांचे को और अधिक सुदृढ़ बनाया जा रहा है। यह आधारभूत संरचना विकास पहल भविष्य में बढ़ने वाले यातायात भार को संभालने की वडोदरा स्टेशन की क्षमता को मजबूत करेगी तथा लाखों रेल यात्रियों के लिए सुरक्षित, सुगम एवं कुशल यात्रा सुनिश्चित करेगी।

VDU आधारित प्रणाली से ट्रेन संचालन का आधुनिकीकरण

यार्ड रीमॉडलिंग परियोजना के अंतर्गत वडोदरा स्टेशन की वर्तमान पारंपरिक पैनल-आधारित प्रणाली को आधुनिक विजुअल डिस्प्ले यूनिट (VDU) आधारित प्रणाली से प्रतिस्थापित किया जा रहा है। यह नई प्रणाली ट्रेन संचालन की निगरानी एवं नियंत्रण को अधिक तेज, सुविधाजनक एवं विश्वसनीय बनाएगी। VDU प्रणाली कंप्यूटर स्क्रीन पर सिग्नलिंग एवं रूट संबंधी जानकारी को स्पष्ट एवं उपयोगकर्ता-अनुकूल स्वरूप में प्रदर्शित करती है, जिससे स्टेशन परिचालन कर्मचारियों को बेहतर दृश्यता, त्वरित रूट सेटिंग तथा शीघ्र निर्णय लेने में सहायता मिलेगी। यह प्रणाली मानवीय त्रुटियों की संभावना को कम करेगी, तकनीकी खामियों की पहचान को आसान बनाएगी तथा परिचालन संरक्षा एवं दक्षता में उल्लेखनीय सुधार लाएगी।

संरक्षा एवं विश्वसनीयता बढ़ाने हेतु डबल स्लिप डायमंड क्रॉसिंग को हटाया जाएगा

संरक्षा को और अधिक मजबूत करने तथा परिचालन को सरल बनाने के लिए मौजूदा डबल स्लिप डायमंड क्रॉसिंग को हटाया जाएगा। यह जटिल ट्रैक संरचना ट्रेनों को एक ही स्थान पर ट्रैक पार करने और मार्ग बदलने की सुविधा प्रदान करती है, लेकिन इसमें अनेक चलित घटक होते हैं, जिनके रखरखाव की आवश्यकता अधिक होती है तथा गति संबंधी प्रतिबंध भी लागू रहते हैं। इसके हटने से ट्रैक संरचना सरल होगी, विश्वसनीयता बढ़ेगी, रखरखाव की आवश्यकता कम होगी तथा स्टेशन यार्ड में ट्रेनों की आवाजाही अधिक सुरक्षित एवं सुगम बनेगी।

प्लेटफॉर्म संख्या 4 एवं 5 का विस्तार

प्लेटफॉर्म संख्या 4 एवं 5 की लंबाई बढ़ाकर इन्हें 22 एलएचबी कोचों वाली ट्रेनों के संचालन हेतु सक्षम बनाया जा रहा है। इस विस्तार से लंबी दूरी की ट्रेनों के सभी कोच प्लेटफॉर्म सीमा के भीतर रहेंगे, जिससे यात्रियों के चढ़ने एवं उतरने की प्रक्रिया अधिक सुरक्षित और सुविधाजनक होगी। साथ ही, भविष्य में बढ़ने वाली यात्री संख्या को ध्यान में रखते हुए लंबी ट्रेनों के संचालन में भी सुविधा मिलेगी।

प्लेटफॉर्म संख्या 5 एवं 6 की बेहतर कनेक्टिविटी

प्लेटफार्म नंबर 5 एवं 6 की रेल लाइन को सीधे मुख्य लाइन से जोड़ा जाएगा, जिससे अनुमत गति 10 किलोमीटर प्रति घंटा से बढ़कर 30 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगी। इस सुधार से डाउन ट्रेनों की प्राप्ति में लगने वाला समय कम होगा तथा परिचालन दक्षता, ट्रेन हैंडलिंग क्षमता एवं समयपालन में सुधार आएगा।

लूप लाइन संख्या 04 एवं 05 पर गति में वृद्धि

लूप लाइन संख्या 04 एवं 05 पर अनुमत गति 10 किलोमीटर प्रति घंटा से बढ़ाकर 15 किलोमीटर प्रति घंटा की जाएगी। इससे यार्ड के भीतर ट्रेनों की आवाजाही अधिक तेज एवं सुगम होगी तथा यार्ड संचालन की दक्षता में वृद्धि होगी।

नई स्टेबलिंग लाइन का निर्माण

परियोजना के अंतर्गत 350 मीटर लंबी नई स्टेबलिंग लाइन का निर्माण भी किया जाएगा, जिससे ट्रेनों के ठहराव एवं रखरखाव कार्यों में सुविधा होगी। यह अतिरिक्त सुविधा ट्रेनों के रेकों की पार्किंग एवं रखरखाव क्षमता बढ़ाएगी, परिचालन लाइनों एवं प्लेटफॉर्मों पर भीड़भाड़ कम करेगी तथा रेक प्रबंधन, सफाई एवं अनुरक्षण कार्यों को अधिक प्रभावी बनाएगी।

आधुनिक स्टेशन मास्टर कार्यालय का निर्माण

परिचालन प्रबंधन एवं कर्मचारियों की कार्यकुशलता बढ़ाने के लिए आधुनिक सुविधाओं, समर्पित कार्यस्थलों एवं भंडारण व्यवस्था से युक्त नया स्टेशन मास्टर कार्यालय भी बनाया जाएगा।

मल्टीमॉडल कनेक्टिविटी को सुदृढ़ करने हेतु नया प्लेटफॉर्म संख्या 7

भविष्य की रेल कनेक्टिविटी को मजबूत बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम के रूप में, NHSRCL द्वारा हाई स्पीड रेल स्टेशन भवन के निकट भारतीय रेलवे के लिए लगभग 15 करोड़ की लागत से प्लेटफॉर्म संख्या 7 का निर्माण किया जाएगा। इस कार्य हेतु निविदा आमंत्रण सूचना (NIT) जारी की जा चुकी है तथा निविदा 23 जुलाई 2026 को खोली जाएगी। प्रस्तावित प्लेटफॉर्म संख्या 7 को ट्रैवलेटर के माध्यम से वडोदरा रेलवे स्टेशन से सीधे जोड़ा जाएगा, जिससे यात्रियों को दोनों परिसरों के बीच सहज आवागमन की सुविधा मिलेगी। यह आगामी हाई-स्पीड रेल स्टेशन के साथ प्रभावी एकीकरण सुनिश्चित करेगा तथा यात्रियों को बेहतर मल्टीमॉडल यात्रा अनुभव प्रदान करेगा। यह प्लेटफॉर्म भारतीय रेलवे के मानकों के अनुरूप विकसित किया जाएगा तथा इसमें प्लेटफॉर्म शेल्टर, पेयजल सुविधा, प्रतीक्षालय, शौचालय एवं टिकट बुकिंग काउंटर सहित सभी आवश्यक यात्री सुविधाएं उपलब्ध होंगी।

विकास एवं आधुनिकीकरण का यह कार्य पश्चिम रेलवे के वडोदरा मंडल की सुरक्षित, आधुनिक एवं यात्री-केंद्रित रेल सेवाएं प्रदान करने की प्रतिबद्धता को पुनः स्थापित करता है। परियोजना पूर्ण होने पर परिचालन गति, संरक्षा, क्षमता, विश्वसनीयता एवं यात्री सुविधाओं में उल्लेखनीय सुधार होगा तथा वडोदरा स्टेशन एक अधिक सक्षम, आधुनिक एवं भविष्य के लिए तैयार रेलवे हब के रूप में विकसित होगा।

अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर अहमदाबाद मंडल की अनूठी पहल

रेलवे इंस्टीट्यूट और सामुदायिक भवनों के साथ-साथ 4 वंदे भारत ट्रेनों में होगा 'योग'

पश्चिम रेलवे के अहमदाबाद मंडल द्वारा 21 जून 2026 को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस-2026 के अवसर पर मंडल के विभिन्न प्रमुख स्थलों तथा चार वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेनों में व्यापक स्तर पर योग सत्रों का आयोजन किया जा रहा है। इस वर्ष का आयोजन न केवल रेलवे परिसरों में बल्कि चलती ट्रेनों में भी यात्रियों को स्वास्थ्य, संतुलित जीवनशैली और समग्र कल्याण के प्रति जागरूक करने के उद्देश्य से किया जा रहा है।

मंडल रेल प्रबंधक श्री वेद प्रकाश के कुशल मार्गदर्शन में आयोजित होने वाले इन कार्यक्रमों के अंतर्गत मुख्य योग सत्र निम्नलिखित प्रमुख स्थलों पर आयोजित किए जाएंगे—

▸▸ सामुदायिक भवन, साबरमती

▸▸ ओल्ड रेलवे इंस्टीट्यूट, साबरमती

▸▸ रेलवे इंस्टीट्यूट, कांकरिया

▸▸ सामुदायिक भवन, गांधीधाम

▸▸ सामुदायिक भवन, वीरमगाम

▸▸ चलती 'वंदे भारत' एक्सप्रेस ट्रेनों में अनूठी पहल

अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस को और अधिक व्यापक एवं जनसुलभ बनाने के उद्देश्य से अहमदाबाद मंडल द्वारा चार प्रतिष्ठित वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेनों में भी विशेष योग सत्र आयोजित किए जाएंगे। इन ट्रेनों में यात्रा कर रहे यात्री योग प्रशिक्षकों के मार्गदर्शन में सीट पर बैठकर किए जाने वाले सरल योगाभ्यास एवं प्राणायाम का अभ्यास कर सकेंगे। इन ट्रेनों का विवरण निम्नानुसार है—

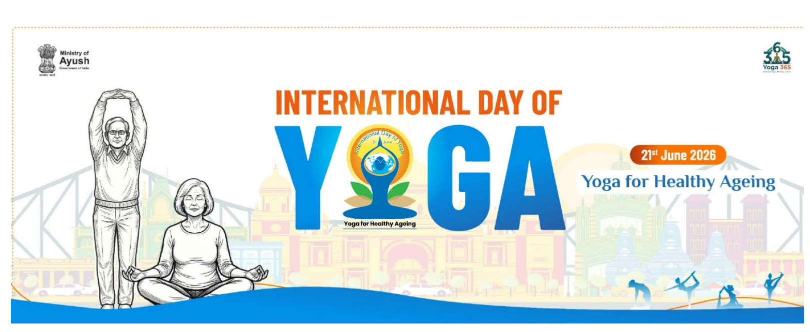

▸▸ गाड़ी संख्या 20902 गांधीनगर कैपिटल – मुंबई सेंट्रल वंदे भारत एक्सप्रेस

▸▸ गाड़ी संख्या 12462 साबरमती – जोधपुर वंदे भारत एक्सप्रेस

▸▸ गाड़ी संख्या 26964 असारवा – उदयपुर वंदे भारत एक्सप्रेस

▸▸ गाड़ी संख्या 22925 अहमदाबाद – ओखा वंदे भारत एक्सप्रेस

अहमदाबाद मंडल द्वारा पूर्व में भी अहमदाबाद, महेसाणा, पालनपुर तथा गांधीधाम सहित विभिन्न प्रमुख स्टेशनों पर योग अभ्यास शिविरों का सफल आयोजन किया जा चुका है, जिसमें रेल कर्मचारियों एवं यात्रियों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया था।

अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस-2026 की थीम "Yoga for Healthy Ageing" के अनुरूप पश्चिम रेलवे का अहमदाबाद मंडल स्वस्थ जीवनशैली और सामूहिक कल्याण के संदेश को जन-जन तक पहुंचाने के लिए प्रतिबद्ध है।

पश्चिम रेलवे अपने सभी सम्मानित रेल यात्रियों एवं रेल कर्मियों से अपील करता है कि वे इन योग सत्रों में सहभागिता कर स्वस्थ जीवन की दिशा में कदम बढ़ाएं तथा इस वैश्विक अभियान का हिस्सा बनें।

एआई द्वारा तैयार किए गए प्रश्न पत्र में केवल उत्तर ही छपे थे, जिसके चलते राजस्थान विश्वविद्यालय ने परीक्षा रद्द कर दी

(छगनलाल मेवाड़ा द्वारा) सूरत। राजस्थान विश्वविद्यालय ने बुधवार, 17 जून को समाजशास्त्र विभाग की द्वितीय सेमेस्टर की परीक्षा रद्द कर दी। छात्रों का आरोप था कि उन्हें कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई) की मदद से तैयार किया गया प्रश्न पत्र दिया गया था, जिसमें प्रश्नों के स्थान पर पहले से लिखे हुए उत्तर थे। "भारतीय समाज" विषय की यह परीक्षा पीजी स्कूल ऑफ ह्यूमैनिटीज में दोपहर 3 बजे से शाम 6 बजे तक होनी थी।

छात्रों ने बताया कि जैसे ही उन्हें प्रश्नपत्र मिला, उन्हें पता चला कि उसमें न तो प्रश्न थे और न ही बहुविकल्पीय प्रश्न। परीक्षा दे रहे छात्र विकास कुमार बैरवा ने आरोप लगाया कि आपत्ति उठाए जाने के बाद परीक्षा हॉल में मौजूद अधिकारियों ने तुरंत प्रश्नपत्र वापस ले लिए। उन्होंने कहा, "प्रशासन ने सभी प्रश्नपत्र वापस ले लिए और छात्रों को बाहर इस मामले पर चर्चा न करने के लिए कहा गया। बाद में हमें केवल इतना बताया गया कि परीक्षा अब 27 जून को होगी।" इस घटना के बाद, छात्रों का एक समूह विश्वविद्यालय प्रशासन भवन के बाहर इकट्ठा हुआ और मामले पर स्पष्टीकरण की मांग की।

एनएसयूआई के पदाधिकारी मनीष मेघवंशी ने बताया कि समाजशास्त्र विभाग के द्वितीय सेमेस्टर की परीक्षा मंगलवार को शुरू होने से पहले ही छात्रों ने प्रश्न पत्रों में गंभीर त्रुटि देखकर उन्हें वापस कर दिया और परीक्षा स्थगित कर दी गई। यह त्रुटि छात्रों के लिए बेहद चौंकाने वाली है। आरोप है कि प्रश्न पत्र कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई) की मदद से तैयार किए गए हैं।